



# मेरी खेती

Page No. 1-33, फ़रवरी 2023



खेत खलियान  
सरकारी नीतियां  
मौसमी व अन्य  
कृषि सुझाव  
सब्जी  
फूल  
औषधीय खेती  
पशुपालन-पशुचारा  
प्रगतिशील किसान

## किसान समाचार



# बागवानी किसानों के लिए समस्या बनती जलवायु परिवर्तन, कैसे बचाएं अपनी उपज

औद्योगिक क्रांति के बाद से पूरे विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग (GLOBAL WARMING) और जलवायु परिवर्तन (CLIMATE CHANGE) केवल मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (ECOSYSTEM) के लिए एक समस्या बनकर उभरा है।

एक समय जिस स्थान पर अच्छी बारिश होती थी आज वहां हर वर्ष सूखा पड़ रहा है, इसका मुख्य कारण जलवायु में परिवर्तन ही है। जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी पर रहने वाले हर प्रजाति को कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान उठाना पड़ता है, इसी नुकसान की वजह से पिछले कुछ वर्षों से फलों के लिए बागवानी खेती करने वाले किसान भाइयों को उपज में काफी कमी देखने को मिली है। उत्तरी भारत के राज्यों में फल उगाने वाले किसान अब नई वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से कुछ उपाय खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 में भारत में लगभग 7 मिलियन हेक्टर क्षेत्र में फल उगाए जाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 93 मिलियन टन फल प्राप्त होते हैं। भारतीय बागवानी कृषि विश्व भर के उत्पाद में लगभग 10% हिस्सेदारी निभाती है। आम, केला और अमरूद तथा अनार, अंगूर और पपीता जैसे प्रमुख फसलों के उत्पादन में भारत विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है।

वैश्विक तापमान में परिवर्तन और बारिश के पैटर्न में हुए बदलाव की वजह से फलदार पौधों में निम्न नुकसानदायक प्रभाव देखने को मिले हैं :

तापमान में वृद्धि होने के कारण किसी भी पौधे पर लगने वाले फलों की परिपक्वता का समय कम हो जाता है। इसकी वजह से वह जल्दी तैयार हो जाते हैं और इन्हें बाजार में जल्दी बेचना पड़ता है, इससे फलों के भंडारण की संभावना कम हो जाती है और उन्हें तुरंत भेजना पड़ता है। इस वजह से किसानों को सही दाम नहीं मिल पाते और उनका मुनाफा कम हो जाता है।

इसके अलावा किसी स्थान पर अधिक वर्षा या सूखा पड़ने पर फसल की उत्पादकता पूरी तरीके से कम होने के साथ ही वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा है, जिस कारण फसल की गुणवत्ता पर काफी बुरा प्रभाव देखने को मिला है।

अधिक कार्बन-डाइऑक्साइड की वजह से फलों में स्टार्च और ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा देखने को मिल रही है, जिससे इन फलों के सेवन से रक्तचाप और शुगर जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ रहा है।

अधिक ग्लूकोज संचित करने वजह से इन फलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है।

इसके अलावा विश्वत रेखा (EQUATORIAL AREA) के आसपास वाले क्षेत्रों में आसमान में अधिक समय तक बादल छाए रहने की वजह से वहां पर उगाए जाने वाले आम और अमरूद के फलों में एस्कोरबिक अम्ल (ASCORBIC ACID) की मात्रा घट जाती है, जिस वजह से फल में पाई जाने वाली मिठास कम हो जाती है और फुल पूरी तरह से फीका लगता है। इस कारण उसकी बाजार मांग में भी कमी देखने को मिलती है।

बदली हुई जलवायु परिस्थितियां नए प्रकार के रोगों को जन्म दे रही है, तापमान में बढ़ोतरी होने से कई सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया पौधों की जड़ों और तने को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके अलावा इन बैक्टीरिया की वृद्धि दर भी तेज हो जाती है, जो बाद में सीधे फलों को ही खाने लगते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए किसानों को रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो लागत को बढ़ाकर आर्थिक दबाव पैदा करते हैं।

हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक विधियों की मदद से इसे कम भले ही किया जा सकता है।

गर्मी के मौसम में पेड़ों की कटाई-छंटाई कम करनी चाहिए और पेड़ के तने और उसकी मोटी शाखाओं को सफेद रंग से पुताई कर देने पर सूरज से आने वाली किरण का प्रभाव कम पड़ता है, जिससे फल के पकने में लगने वाला समय अधिक हो जाता है और किसान को अच्छी उपज के साथ ही अच्छा मुनाफा हो पाता है।

अधिक गर्मी पड़ने से बाग के क्षेत्र में नमी की मात्रा कम हो जाती है। नमी को बरकरार बनाए रखने के लिए समय-समय पर क्षेत्र की नमी की जांच करनी चाहिए और बाग की नियमित और उचित सीमित मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए।

यदि आप के बाग में पिछले सीजन के कुछ पौधे बचे हुए हैं और उनसे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें काटकर उनकी पलवार बना देनी चाहिए, जिससे बाग के क्षेत्र के तापमान को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक खाद का इस्तेमाल करने से पौधों में नमी बनी रहती है और उन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है। इससे रासायनिक उर्वरक खरीदने का खर्चा भी बच जाता है।

अधिक ठंड पड़ने वाले क्षेत्रों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए पतझड़ के समय पौधों के नीचे गिरी हुई सूखी टहनियों और पत्तियों को इकट्ठा कर जलाने से भी फायदा हो सकता है।

इसके अलावा पत्तियों को जलाने से होने वाले धुआं की वजह से कई प्रकार के छोटे कीट और फल मक्खी पौधों से दूर भाग जाते हैं, इससे आपकी फलों की निरन्तर सुरक्षा भी हो पाती है।

फलों की छोटी पौध को हमेशा पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करते हुए लगाना चाहिए, इससे सूरज की किरणों का कम प्रभाव पड़ता है।

दिलीप यादव  
मेरी खेती

सरसों की खेती से होगी धन की बरसात,  
यहां जानिये वैज्ञानिक उपाय जिससे हो सकती है बंपर पैदावार



## कानपूर आईआईटी द्वारा विकसित कम जल खपत में अधिक पैदावार करने वाला गेंहूँ का बीज

साल 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार मिलेट्स के क्षेत्रफल को बढ़ाएगी। प्रदेश सरकार इस रकबे को 11 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 25 लाख तक करेगी। राज्य सरकार ने अपने स्तर से तैयारियों का शुभारंभ कर दिया है। आने वाले साल 2023 को दुनिया मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाएगी। मिलेट्स वर्ष मनाए जाने की पहल एवं इसकी शुरुआत में भारत सरकार की अहम भूमिका रही है। भारत में मिलेट्स का उत्पादन अन्य सभी देशों से अधिक होता है।

देश का मोटा अनाज पूरी दुनिया में अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोटे अनाज को उत्सव के तौर पर मनाकर देश की प्रसिद्धि को दुनियाभर में फैलाना चाहते हैं। कुछ ही दिन पहले मोदी जी ने दिल्ली में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में मोटे अनाज का बना हुआ खाना खाया था। भारत के विभिन्न राज्यों में मोटा अनाज का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। मिलेट्स इयर आने की वजह से उत्तर प्रदेश राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन का क्षेत्रफल बाढ़ गया है।

## उत्तर प्रदेश राज्य कितने हेक्टेयर में करेगा मोटे अनाज का उत्पादन

खबरों के मुताबिक, प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मिलेट्स इयर के संबंध में राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इस विषय पर बैठक की है। इस बैठक में जिस मुख्य विषय पर चर्चा की गयी वह यह था, कि वर्तमान में 11 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज का उत्पादन हो रहा है। इसको साल 2023 में 25 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाए। हालाँकि लक्ष्य थोड़ा ज्यादा बड़ा है, विभाग के अधिकारी पहले से ही इस बात के लिए तैयारी में जुट जाँएँ।

## उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना लक्ष्य तय किया है

राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थों को आगामी वर्ष में मोटे अनाज का क्षेत्रफल दोगुने से ज्यादा वृद्धि का आदेश दिया है। बता दें, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज से संबंधित पहल को बेहद ही गहनता पूर्वक लिया गया है। साथ ही, इस विषय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी काफी गंभीरता दिखा रही है। उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्रफल का इलाका 86 फीसद है। बता दें, कि इस रकबे में दलहन, तिलहन, धान, गेहूँ का उत्पादन किया जाता जाती है।

## कहाँ से खरीदेगी सरकार बीज

कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, कि कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के अधिकारियों से संपर्क साधें। राज्य में बुआई हेतु मोटे अनाज के बीज की बेहतरीन व्यवस्था की जाए। सबसे पहली बार 18 जनपदों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बाजरा खरीदा जा रहा है।

## उत्तर प्रदेश में कितना किया जायेगा अनाज का उत्पादन

उत्तर प्रदेश के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश में मोटे अनाज की मुख्य फसलें जिनका अच्छा उत्पादन भी होता है, वह ज्वार एवं बाजरा हैं। महाराष्ट्र राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बाजरा का उत्पादन किया जाता है। क्षेत्रफलानुसार बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 9.04 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 6.88, राजस्थान में 43.48 लाख हेक्टेयर में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। वहीं, उत्तर प्रदेश राज्य की पैदावार प्रति हेक्टेयर 2156 किलो ग्राम है। राजस्थान का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 1049 किलोग्राम एवं महाराष्ट्र की पैदावार की बात करें तो 955 किलो ग्राम है।



## ज्वार के उत्पादन का क्षेत्रफल कितना बढ़ा है

राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में ज्वार का अच्छा खासा उत्पादन होता है। क्षेत्रफल के तौर पर कर्नाटक प्रति हेक्टेयर प्रति किंटल पैदावार के मामले में अक्वल स्थान है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ज्वार की पैदावार बढ़ाने के लिए काफी जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में 1.71 लाख हेक्टेयर उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन वर्ष 2023 में इसको 1.71 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2.24 लाख हेक्टेयर तक पहुँचा दिया है। इसी प्रकार सावां व कोदो का रकबा भी पहले से दोगुना कर दिया गया है।

## 2. सफेद रतुआ

यह लक्षण- पौधे के पत्तों, टहनियों, तनों, फूलों, और फलियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर सफेद दाने और ऊपरी पत्ती की सतह पर पीले रंग का पीलापन दिखाई देता है। बाद की अवस्था में, पीले प्रभामंडल के साथ दाने गाढ़े रूप में दिखाई दे सकते हैं। जब युवा तना और पुष्पक्रम संक्रमित होते हैं, तो कवक प्रणालीगत हो जाता है और पौधों में विकृतियों को उत्तेजित करता है। सफेद रतुआ बीमारी फलियों व तने पर अधिक आती है। इससे तना सिकुड़ जाता है। इससे फसल के उत्पादन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। सफेद रतुआ का प्रकोप ज्यादातर पिछेती फसल में होता है।

## उपचार और प्रबंधन

1. समय से बुवाई करें (10-25 अक्टूबर), फसल के अवशेषों को नष्ट करें, विशेष रूप से पिछली फसलों के अवशेषों को।
2. रोगमुक्त बीजों का प्रयोग करें, बीज को एग्रन 35एसडी @ 6 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें, फसल की अधिक सिंचाई से बचें।
3. फसल पर डाइथेन एम-45 @ 0.2% का छिड़काव करें और 15 दिनों के अंतराल पर दोहराएं या सफेद रतुआ आने पर खेत में मैनकोजैब दवाई 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी मिलाकर अवश्य स्प्रे करें व दूसरा स्प्रे 15 दिन के बाद करें।

## 3. डाउनी मिल्ड्यू

इसका पहला लक्षण नयी पत्तियों पर जामुनी कर्थई धब्बों के रूप में प्रकट होता है। पत्ती की ऊपरी सतह पर घाव हलके रंग से लेकर पीले रंग का होता है, इन घावों की निचली सतह पर आमतौर पर कवक की कोमल वृद्धि दिखाई देती है। प्रणालीगत संक्रमण में, सफेद जंग के रूप में लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं। रोग जायदा फैलने पर फूलों के गुच्छे बन जाते हैं और फूल फली बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। इस रोग से फसल की पैदावार कम हो जाती है।

## उपचार और प्रबंधन

फसल अवशेषों को नष्ट करें, रोगमुक्त बीजों का प्रयोग करें, बीज को एग्रन एसडी 35 @ 6 ग्राम/किलो बीज से उपचारित करें, फसल पर डाइथेन एम-45 @ 0.2% का छिड़काव करें।

## 4. पाउडर फफूंदी

इस रोग के लक्षण पत्तियों की ऊपरी, निचली सतह और पौधे के अन्य ऊपरी भागों पर सफेद चूर्ण जैसा दिखाई देते हैं। इस रोग के कारण होने वाली उपज हानि फसल के संक्रमण की अवस्था पर निर्भर करती है। यदि फसल के विकास के प्रारंभिक चरण में रोग फसल को संक्रमित करता है, तो नुकसान भारी होता है। रोग आमतौर पर बुवाई के बाद देर से प्रकट होता है। गंभीर संक्रमण में, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, जिससे समय से पहले पत्तियाँ झड़ जाती हैं और जबरन परिपक्वता आ जाती है।

## उपचार और प्रबंधन

1. मई-जून के दौरान गहरी जुताई करें और फसल चक्र का पालन करें।
2. समय से बुवाई करें और देर से बोने से बचें, फसल के अवशेषों को जला दें, रोग की शुरुआत के समय वेटेबल सल्फर @ 0.2% या कैराथेन @ 0.1% का छिड़काव करें।

## सरसों की फसल में प्रमुख रोग और रोगों का प्रबंधन

## सरसों की फसल में प्रमुख रोग और रोगों का प्रबंधन

सरसों की फसल भारत में तिलहन के रूप में लगायी जाती है सरसों के तेल का इस्तेमाल भी भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है। भारत में सरसों की फसल की पैदावार अच्छी होती है पर रोगों के कारण फसल की पैदावार घटती रहती है। रोगों के कारण किसानों की फसल की पैदावार कम हो जाती है जिससे किसानों को नुकसान होता है इस नुकसान को कम करने के लिए आपको सही समय पर फसल में रोग प्रबंधन करना जरूरी है। हमारे इस लेख के माध्यम से आप सरसों की फसल में रोगों की पहचान और उनके उपचार के बारे में जानेंगे।

### 1. अल्टरनेरिया ब्लाइट

यह लक्षण - सरसों की फसल में अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट के नाम से सबसे पहले पत्तियों पर दिखाई देती है। जिसमें छोटे, गहरे भूरे या काले धब्बे पीले प्रभामंडल और केंद्रित, लक्ष्य-जैसे छल्ले के साथ दिखाई देते हैं। संकेंद्रित वलय वाले गोल धब्बे होते हैं कई धब्बे आपस में मिलकर बड़े-बड़े धब्बे बना लेते हैं। पत्तियों को झुलसा देते हैं और झड़ जाते हैं रोग के लक्षण पहले निचली और पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं धब्बे तनों और फूलों पर भी दिखाई देते हैं। इस रोग के कारण बीज सिकुड़े हुए और छोटे आकार के हो जाते हैं।

### उपचार और प्रबंधन

1. बुवाई के लिए स्वस्थ बीजों के प्रयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2. जैसे ही पौधों पर लक्षण दिखाई देने लगे मैनकोजेब 75 डब्ल्यूपी 2kg की दर से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें।
3. फसल की कटाई के बाद प्रभावित पौधों के हिस्सों को इकट्ठा करके जला दें।





## 5. तना गलन या ओगल

इस रोग के लक्षण बढ़े हुए और पानी से भरे हुए होते हैं इसके घाव ज्यादातर तने पर विकसित होते हैं। जो कॉटनी मायसेलियल ग्रोथ से ढके होते हैं, केंद्रीय तना पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और सफेद कवक जाल से भर जाता है जो बाद में सख्त हो जाता है और काला स्कलेरोशिया बनता है। कवक के काले अनियमित शरीर प्रभावित पौधों पर या अंदर देखे जा सकते हैं। प्रभावित पौधों में बौनापन और समय से पहले पकने के लक्षण दिखाई देते हैं। ज्यादा संक्रमण होने पर तने का टूटना, मुरझाना और सूखना दिखाई देता है।



## उपचार और प्रबंधन

1. गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करें, बिजाई के लिए स्कलेरोटियल मुक्त बीज का प्रयोग करें।
2. गैर-मेज़बान फ़सलों जैसे जौ, गेहूँ के साथ फ़सल चक्रीकरण करें, फसल अवशेषों को नष्ट करें।
3. कार्बेन्डाजिम @ 0.2% के साथ बीज उपचार के बाद कार्बेन्डाजिम @ 0.1% के दो छिड़काव बुवाई के 45 और 60 दिनों के बाद करें।





ब्रोकली की  
खेती कर हरदोई  
के किसान हो  
रहे हैं मालामाल

सुशील मौर्य से मिली जानकारी से हमें पता चला है, कि वह साल 2017 से ही सब्जी की खेती कर रहे हैं। फसल की सबसे अच्छी बात है, कि उन्हें पहले साल में ही इससे मुनाफा मिलना शुरू हो गया था। पहले उन्हें कस्बे के बाजार में इसके लिए अच्छे खरीदार नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने इस सब्जी को हरदोई की सब्जी मंडी तक पहुंचाया जहां पर उन्हें अपनी फसल का बहुत ही उचित दाम मिला। इसके बाद एक दिन उन्होंने लखनऊ जा रही पिकअप ट्रांसपोर्ट के जरिए अपनी फसल लखनऊ भेजी और वहां से मिले फायदे से तो मानो उनकी जेब नोटों से ही भर गई। लखनऊ से लौटकर इस सब्जी की खेती बड़े स्तर पर शुरू कर दी। अब कई व्यापारी खेत से ही इस ले जाते हैं, इस सब्जी का बाजार भाव समय के अनुसार 100 से 200 रुपये किलो तक मिल जाता है।

### ठंडी जलवायु में पैदा होती है यह फसल

उद्यान विभाग के अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि, गोभी की तरह दिखने वाली इस ब्रोकली को बड़े बड़े मॉल एवं बड़े बड़े बाजारों में बहुत ही उचित दाम पर बेचा जाता है। इसके अलावा बहुत से पांच सितारा होटल में भी इसकी सब्जी और सलाद बड़े ही चाव से खाया जाता है। ब्रोकली की नर्सरी के लिए सबसे उत्तम महीना सितंबर, अक्टूबर और जनवरी माना जाता है। वैसे इसे अब किसान अपनी सुविधा के अनुसार 12 माह उगा रहे हैं। किसान सही वातावरण के अनुसार इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। ब्रोकली की खेती के लिए 15 से 25 डिग्री के बीच तापमान उचित माना जाता है। यह ठंडी जलवायु में पैदा होने वाली सब्जी की फसल है।

### फूलगोभी की तरह ही तैयार हो जाती है नर्सरी

हो सकता है यह आपने पहली बार सुना हो लेकिन ब्रोकली 3 रंगों में होती है, जिसमें बैंगनी, सफेद और हरा शामिल है। इसकी किस्मों में पेरिनियल, नाइन स्टार और इटालियन ग्रीन जैसी कई उन्नतशील किस्में शामिल हैं। हरदोई के किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर रहे हैं और इसकी सबसे अच्छी बात है, कि आप फूलगोभी की तरह इस की नर्सरी तैयार कर सकते हैं।

## ब्रोकली की खेती कर हरदोई के किसान हो रहे हैं मालामाल

उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। आज उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में किसान सब्जियां उगा कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। यहां पर सबसे खास बात यह है, कि यहां के किसान अब इस तरह की सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं, जिनका भारी माला में विदेशों से आयात किया जाता है। इस तरह की सब्जियों में सबसे खास सब्जी है ब्रोकली। ब्रोकली का नाम किसने नहीं सुना होगा, आजकल लोग भारी माला में सब्जी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक मानी गई है। ब्रोकली को कैंसर जैसी बीमारी से बचाने के लिए सहायक माना गया है, साथ ही इसमें प्रोटीन भी काफी ज्यादा माला में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जिले हरदोई के किसान भारी माला में इस सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं।

हरदोई के कोथावा ब्लॉक के तेरवा पतसेनी निवासी किसान सुशील मौर्य पहले एक साधारण किसान थे। वह अपनी पुश्तैनी खेती की जमीन पर धान- गेहूं जैसी फसल उगा कर अपना गुजारा चला रहे थे। यहां के किसान सुशील बताते हैं, कि 2017 में हरदोई में स्थित गांधी भवन में उद्यान विभाग द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें अलग-अलग तरह की सब्जियों के स्टाल लगाए गए थे। यहां पर किसानों को अलग-अलग तरह की सब्जियां उगाने के बारे में जागरूक किया गया था तो वहीं पर सुशील मौर्य ने पहली बार गोभी जैसी दिखने वाली है हरी सब्जी देखी थी। जब उन्होंने सुपरवाइजर से पूछा कि यह कौन सी सब्जी है तो उनका उत्तर था कि यह ब्रोकली है।

### भारत में भी किसान कर रहे हैं ब्रोकली की खेती

उत्तर प्रदेश के किसान सुशील मौर्य से बातचीत में पता चला कि वह अब ब्रोकली की खेती कर रहे हैं और इससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। साथ ही, उन्होंने हमें यह भी जानकारी दी कि जब उन्हें इस खेती के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी तो उन्होंने उद्यान विभाग से संपर्क किया और वहां के अधिकारी सुरेश कुमार ने उन्हें अच्छी तरह से ब्रोकली की खेती और उससे मिलने वाले मुनाफे के बारे में जानकारी दी। एक बार जानकारी मिल जाने के बाद उन्होंने इसकी खेती शुरू की और अब वह लाखों में कमाई कर रहे हैं।





किसान नवीन तकनीक से उत्पादन कर आलू, मूली और भिंडी से कमाएं बेहतरीन मुनाफा

## किसान नवीन तकनीक से उत्पादन कर आलू, मूली और भिंडी से कमाएं बेहतरीन मुनाफा

फिलहाल मंडी में आलू, भिंडी एवं मूली का समुचित भाव प्राप्त करने के लिए काफी मशक्कत करनी होती है। अगर किसान नई तकनीक और तरीकों से कृषि करते हैं, तो वह अपनी पैदावार को अन्य देशों में भी भेज करके बेहतरीन मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। वर्तमान दौर में खेती-किसानी ने आधुनिकता की ओर रुख कर लिया है, जिसकी वजह से किसान अपने उत्पादन से मोटी आमदनी भी करते हैं। किसानों को यह बात समझने की बहुत जरूरत है, कि पारंपरिक तौर पर उत्पादन करने की जगह किसान विज्ञान व वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार खेती करें। क्योंकि किसानों की इस पहल से वह कम खर्च करके अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, साथ ही, किसानों को नवाचार की अत्यंत आवश्यकता है। अगर न्यूनतम समयावधि के अंतर्गत किसान कृषि जगत में प्रसिद्धि एवं धन अर्जित करना चाहते हैं तो किसानों को बेहद जरूरत है कि वह नवीन रूप से कृषि की दिशा में अग्रसर हों। किसान उन फसलों का उत्पादन करें जो कि बाजार में अपनी मांग रखते हैं साथ ही उनसे अच्छा लाभ भी मिल सके।

किसान हरी भिंडी की जगह लाल भिंडी, सफेद मूली के स्थान पर लाल मूली एवं पीले आलू की बजाय नीले आलू का उत्पादन करके किसान अपना खुद का बाजार स्थापित कर सकते हैं। इस बहुरंगी कृषि से किसान बेहद मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी वजह यह है, कि इन रंग बिरंगी सब्जियों की मांग बाजार में बहुत ज्यादा रहती है। परंतु फिलहाल भारत में भी सब्जियां केवल खाद्यान का माध्यम नहीं हैं, वर्तमान में इनकी बढ़ती मांग से किसान सब्जियों को विक्रय कर बहुत मोटा लाभ कमा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी लाल भिंडी में कैल्शियम, जिंक एवं आयरन जैसे तत्व प्रचूर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गुणों से युक्त होने की वजह से बाजार में इस भिंडी का भाव 500 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अर्जित होता है। यह साधारण सी फसल आपको बेहतरीन मुनाफा प्रदान कर सकती है।

### नीले आलू के उत्पादन से कमाएं मुनाफा

हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं, कि आलू की फसल को सब्जियों का राजा कहा जाता है। इसलिए आलू प्रत्येक रसोई में पाया जाता है, आजतक आपने सफेद या पीले रंग के बारे में सुना होगा और खाए भी होंगे। परंतु फिलहाल बाजार में आपको नीले रंग का आलू भी देखने को मिल जायेगा, बहुत सारे पोषक तत्वों से युक्त है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, मेरठ के वैज्ञानिकों ने नीले रंग के आलू की स्वदेशी किस्म को विकसित कर दिया है। इस किस्म को कुफरी नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, इस आलू में एंथोसाइनिन एवं एंटी-ऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। एक हैक्टेयर में नीले आलू की बुवाई करने के उपरांत किसान 90 से 100 दिन की समयावधि में तकरीबन 400 क्विंटल तक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीला आलू दोगुने भाव में विक्रय हो बिकता है, इस अनोखी सब्जी के उत्पादन से पूर्व मृदा परीक्षण करके कृषि वैज्ञानिकों से सलाह-जानकारी ले सकते हैं।

### लाल मूली के उत्पादन से होगा लाभ

मूली एक ऐसी फसल है, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है। मूली का उपयोग घर से लेकर ढाबे तक सलाद के रूप में किया जाता है। परंतु वर्तमान दौर में अन्य सब्जियों की भांति मूली का रंग भी परिवर्तित हो गया है। आपको बता दें कि आजकल बाजार में लाल रंग की मूली भी उपलब्ध है। लाल रंग की मूली का उत्पादन सर्दियों के दिनों में किया जाता है। जल-निकासी हेतु अनुकूल बलुई-दोमट मिट्टी लाल मूली के उत्पादन हेतु सबसे बेहतरीन मानी जाती है। किसान नर्सरी में भी लाल मूली की पौध को तैयार कर इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मूली कतारों में उत्पादित की जाती है। इसकी 40 से 60 दिनों के अंदर किसान कटाई कर सकते हैं, जिससे 54 क्विंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। साधारण-सफेद मूली का बाजार में भाव 50 रुपये प्रति किलोग्राम होता है। परंतु देश-विदेश में लाल रंग की मूली का भाव 500 से 800 रुपये किलोग्राम है।





यह अमरुद किसानों की अच्छी आमदनी करा सकता है

## यह अमरुद किसानों की अच्छी आमदनी करा सकता है

वर्तमान में चल रही बाजार मांग और बेहतर उत्पादन देने वाली सब्जियों का चयन करना किसानों के लिए मुनाफा दायक हो सकता है।

वर्तमान में भारतीय बाजार में लोकप्रिय और अक्टूबर महीने के शुरुआती दिनों में उगाई जा सकने वाली सब्जियां जैसे कि सेलेरी, स्विस् चार्ड तथा लाल पत्ता गोभी और चाइनीस पत्ता गोभी के अलावा ब्रोकली जैसी सब्जियां प्रमुख है।

यदि कोई किसान भाई गर्मियों के समय में पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चेरी टमाटर, बेबीकॉर्न और शिमला मिर्च उगाना चाहता है तो इन की बुवाई अप्रैल महीने की शुरुआत में की जा सकती है।

## इस अमरुद की खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, वर्तमान में केवल हरे, पीले एवं इलाहाबादी की भाँति लाल अमरुद देखने को मिले होंगे। जो कि पारंपरिक खेती हैं। परंतु, यदि अमरुद का उत्पादन नवीनतम ढंग से किया जाए तो काला अमरुद उसके लिए अच्छा चयन है। काला अमरुद आने वाले समय में अत्यधिक मांग के साथ बाजार में अपना स्थान बनाएगा। भारतीय जलवायु व मृदा काले अमरुद के उत्पादन हेतु काफी अनुकूल है। आगामी दौर में पीले, हरे के उपरांत काले अमरुद की बाजार में अच्छी खासी माँग रहेगी। आपको बता दें कि आगामी समय में काले अमरुद की अत्यधिक मांग होने के साथ-साथ अच्छे मुनाफे की भी संभावना है।

## काले अमरुद का उत्पादन किस समय किया जाता है

विशेषज्ञों के अनुसार, अमरुद का उत्पादन करने के लिए ठंडी जलवायु व मौसम होना काफी आवश्यक होता है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अत्यधिक मोसमिक नमी फसल के लिए फायदेमंद नहीं होती है। सर्द मौसम में यदि अमरुद की खेती की जाए तो अमरुद के पैदावार काफी बेहतर हो सकती है। साथ ही, उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन, यदि किसान सामान्य मृदा में भी अमरुद की खेती करना चाहें तो कर सकते हैं।

## कितने वर्ष उपरांत अमरुद लगने लगता है

अमरुद की खेती में यदि आप समुचित उर्वरक व सिंचाई इत्यादि करें, तो इसका विकास अच्छा और शीघ्र होता है।

कृषकों को उचित समयानुसार अमरुद की कटाई, छंटाई भी होनी जरूरी होती है। आपको बता दें कि बुवाई करने के उपरांत दो से तीन वर्ष उपरांत पेड़ पर अमरुद लगना आरंभ हो जाते हैं। अमरुद की फसल की देखभाल करने में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कीट रोगों के संक्रमण के दौरान विशेषज्ञों से सलाह मशवरा लेकर ही कीटनाशकों का छिड़काव अवश्य कर देना चाहिए। अमरुद को पककर तैयार होने के बाद कटाई में समय नहीं लगाना चाहिए।

## काले अमरुद की खेती कहाँ-कहाँ हो रही है

वर्तमान में सुझाई गई वैज्ञानिक तकनीकों के तहत ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल कर कीट और रोगों से बचा जा सकता है।

ग्रीन हाउस विधि से मृदा और बीजजनित रोग जैसे किडंपिंग ऑफ तथा ब्लैक रोट आदि से बचा जा सकता है।

इन रोगों की रोकथाम के लिए डाईथेन- एम नामक रसायन का इस्तेमाल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर किया जा सकता है।

## विदेशी सब्जियों की कटाई के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां :-

कुछ पत्तेदार विदेशी सब्जियां की कटाई की शुरुआत पौधरोपण के 50 दिनों के अंतर्गत कर लेनी चाहिए। इससे अधिक समय होने पर पत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट आती है और सब्जी का स्वाद भी धीरे-धीरे खत्म होता जाता है।

सुबह के समय सब्जी के पत्तियों की तुड़ाई करना सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय पत्तियों के पर्ण में पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है और उन्हें तोड़ने के बाद लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है।

एक बार पत्तियों की तुड़ाई करने के बाद पौधे की पुनः वृद्धि के लिए बेहतर जैविक खाद का प्रयोग कर मृदा में मिला देना चाहिए। चेरी टमाटर और शिमला मिर्च जैसी विदेशी सब्जियों के उत्पादन के दौरान परिवहन के समय को कम रखना चाहिए, क्योंकि परिवहन में लगने वाले समय के दौरान इनका रंग हरे से लाल हो जाता है, इसलिए इनकी तुड़ाई उसी समय करनी चाहिए जब फल परिपक्व होने शुरू हो जाए, नहीं तो सब्जी की बिक्री में गिरावट हो सकती है।

आशा करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्य में रहने वाले किसान भाइयों को Merikheti.com के द्वारा उपलब्ध करवाई गई 'वैज्ञानिक विधि से विदेशी सब्जी उत्पादन' की यह जानकारी पसंद आई होगी और आप भी भविष्य में बेहतर पौधशाला निर्माण और उर्वरकों के सही प्रबंधन की मदद से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे।







## किन वजहों से लद्दाख के इस फल को मिला जीआई टैग

### किन वजहों से लद्दाख के इस फल को मिला जीआई टैग

दरअसल, लद्दाख में 30 से भी ज्यादा प्रजाति की खुबानी का उत्पादन किया जाता है, परंतु रक्तसे कारपो खुबानी स्वयं के बेहतरीन गुण जैसे मीठा स्वाद, रंग एवं सफेद बीज के कारण काफी प्रसिद्ध है। कारपो खुबानी को 20 वर्ष उपरांत 2022 में जीआई टैग हाँसिल हुआ है। बता दें, कि लद्दाख की ठंडी पहाड़ी, जहां जन-जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। रक्तसे कारपो खुबानी इसी क्षेत्र में उत्पादित होने वाली फसल को भौगोलिक संकेत मतलब कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह खुबानी लद्दाख का प्रथम जीआई टैग उत्पाद है, इसके उत्पादन को फिलहाल कारगिल में 'एक जिला-एक उत्पाद' के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी मध्य बहुत सारे लोगों को यह जिज्ञासा है, कि लद्दाख में उत्पादित होने वाली इस रक्तसे कारपो खुबानी की किन विशेषताओं की वजह से, इसको सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि रक्तसे कारपो खुबानी फल एवं मेवे की श्रेणी में दर्ज हो गया है, क्योंकि रक्तसे कारपो खुबानी अन्य किस्मों की तरह नहीं होता इसके बीज सफेद रंग के होते हैं।

### रक्तसे कारपो खुबानी की क्या विशेषताएं हैं

विशेषज्ञों का कहना है, कि लद्दाख की भूमि पर उत्पादित की जाने वाली खुबानी रक्तसे कारपो की सबसे अलग विशेषता इसके सफेद रंग के बीज हैं, जो कि पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। किसी भी क्षेत्र के खुबानी में विशेष बात यह है, कि खुबानी की ये प्रजाति सफेद रंग के बीजयुक्त फलों के मुकाबले अधिक सोर्बिटोल है। जिसे उपभोक्ता ताजा उपभोग करने हेतु सर्वाधिक उपयोग में लेते हैं। लद्दाख में उत्पादित की जाने वाले 9 फलों में रक्तसे कारपो खुबानी का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्योंकि लद्दाख की मृदा एवं जलवायु इस फल के उत्पादन हेतु अनुकूल है। यहां के खुबानी फल की मिठास एवं रंग सबसे भिन्न होता है।

### लद्दाख में होता है, सबसे ज्यादा खुबानी उत्पादन

देश में लद्दाख के खुबानी को सर्वाधिक उत्पादक का खिताब हाँसिल हुआ है। लद्दाख में प्रति वर्ष 15,789 टन खुबानी का उत्पादन होता है, जो कि देश में कुल खुबानी उत्पादन का 62 प्रतिशत भाग है। वर्ष 2021 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने से पूर्व स्थायी कृषक थोक में खुबानी का विक्रय करते थे। बाजार में इसका समुचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता था। परंतु अब खुबानी को अन्य देशों में भी भेजा जाता है, इस वजह से यहां के कृषकों को बेहद लाभ प्राप्त हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है, कि लद्दाख की खुबानी को तैयार होने में कुछ वक्त लगता है। यहां जुलाई से सितंबर के मध्य खुबानी की कटाई कर पैदावार ले सकते हैं।

### खुबानी से होने वाले लाभ

खुबानी एक फल के साथ-साथ ड्राई फ्रूट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यदि हम इसके लाभ की बात करते हैं, तो लद्दाख खुबानी में विटामिन-ए, बी, सी एवं विटामिन-ई सहित कॉपर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि भी विद्यमान होते हैं। साथ ही, खुबानी में फाइबर की भी प्रचूर मात्रा उपलब्ध होती है। यदि हम खुबानी का प्रतिदिन उपभोग करते हैं, तो आंखों की समस्या, डायबिटीज एवं कैंसर जैसे खतरनाक व गंभीर रोगों का प्रभाव कम होता है। साथ ही, समयानुसार उपयोग की वजह से कॉलेस्ट्रॉल भी काफी हद तक नियंत्रण में रहता है। खुबानी को आहार में शामिल करने से हम त्वचा संबंधित परेशानियों से भी निजात पा सकते हैं। खुबानी का प्रतिदिन उपभोग करने से शरीर में आयरन की मात्रा में कमी आ जाती है, एवं खून को बढ़ाने में सहायक साबित होती है।





## वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयास से इस राज्य के गाँव में हुआ केसर का उत्पादन



## वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयास से इस राज्य के गाँव में हुआ केसर का उत्पादन

कश्मीर केसर की पैदावार के मामले में अलग ही पहचान रखता है। पहली बार इसका उत्पादन सिक्किम के एक गाँव में किया गया था। वैज्ञानिक अब इस फसल का रकबा मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश की तरफ विस्तृत कर रहे हैं। केसर सुगंध एवं औषधीय गुणों की विशेषता की वजह से जानी जाती है। भारत का कश्मीर बड़े पैमाने पर केसर की फसल का उत्पादन करता है। कश्मीर का केसर देश के साथ-साथ दुनियाभर में अपनी बेहतरीन पहचान रखता है। केंद्र सरकार द्वारा बीते काफी वक्त से केसर की खेती का रकबा बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। साथ ही, केसर का उत्पादन कश्मीर के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी किया जाना चाहिए। फिलहाल वैज्ञानिकों द्वारा अद्भुत कार्य कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कश्मीर के अलावा भी अन्य राज्यों में केसर की फसल होगी।

### सिक्किम के किस गाँव में की गयी केसर की खेती

मीडिया खबरों के मुताबिक, वैज्ञानिक काफी वक्त से प्रयासरत थे, कि कश्मीर के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों में भी केसर की पैदावार की जा सके। साथ ही इसके रकबे को बढ़ाने में भी लगे हुए थे। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च द्वारा बहुत पहले से इस विषय पर शोध किया जा रहा था। नतीजतन दक्षिण सिक्किम में उपस्थित यांगतांग गाँव में प्रथम बार केसर का सफलतापूर्वक उत्पादन एवं खेती हुई है। सामने आये परिणामों की वजह से वैज्ञानिक बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं।

### इन राज्यों में बढ़ाया जायेगा केसर का उत्पादन

सिक्किम के उपरांत वैज्ञानिक फिलहाल दूसरे प्रदेशों तक बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत हैं। आज केसर की बुवाई अरुणाचल प्रदेश में तवांग एवं मेघालय के बारापानी तक विस्तृत की जा रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक, बहुत वक्त पूर्व सिक्किम सरकार द्वारा अपने राज्य के अलग अलग इलाकों में केसर की खेती की जाने की संभावना देखी गयी। क्योंकि सिक्किम की भूमि केसर की खेती हेतु उपयुक्त मानी गयी है। बता दें, कि पूर्वी सिक्किम में खमडोंग, पदमचेन, पंगतांग, सिमिक एवं समीपवर्ती इलाकों को केसर की बुवाई हेतु चिन्हित किया गया है। सिक्किम के अधिकारियों द्वारा जम्मू कश्मीर में पहुँच केसर की स्थिति का मुआयना किया जा चुका है।

### जानिए किस वजह से हो रही है केसर की खेती सफल

जम्मू कश्मीर एवं सिक्किम के बागवानी विभाग के अधिकारी केसर की पैदावार को लेकर निरंतर संपर्क साधे हुए हैं। इसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, किसी भी फसल का उत्पादन पर्यावरण पर काफी ज्यादा निर्भर होता है। यदि हम केसर की खेती के बारे में बात करें तो कश्मीर एवं सिक्किम मौसमिक एवं भौगोलिक दृष्टि से एक समान ही हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक, अधिकारिक रूप से यह सिद्ध किया गया है, कि सिक्किम सरकार द्वारा करीब डेढ़ एकड़ रकबे में केसर का उत्पादन किया जाता है। जिसका अच्छा खासा परिणाम भी देखने को मिला है।

### जमीन के छोटे से भाग में किया गया केसर का उत्पादन

मीडिया खबरों के मुताबिक, सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद ने बताया था, कि मिशन 2020 में सिक्किम विश्वविद्यालय की निगरानी में जमीन के छोटे से भाग पर केसर का उत्पादन किया गया था। परिणामस्वरूप उस भूमि में बेहद अच्छा उत्पादन भी हुआ था। परिणामों को देखने के बाद केसर को अन्य राज्यों के दूसरे हिस्सों में बोनो का फैसला लिया गया है। प्रदेश में 80 फीसद की दर से केसर का उत्पादन हुआ है।



बागवानी के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर हर किसान कर सकता है अपनी कमाई दोगुनी



## बागवानी के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर हर किसान कर सकता है अपनी कमाई दोगुनी

आजकल पारंपरिक तरीकों से खेती करते हुए किसान मुनाफा तो कमाते हैं। लेकिन अगर वह ज्यादा आमदनी कमाना चाहते हैं, तो केवल पारंपरिक तरीके की खेती करना इसका हल नहीं है। सरकार और सभी तरह के कृषि वैज्ञानिक लगातार इस चीज के पीछे प्रयासरत रहते हैं, कि किसान किसी ना किसी तरह से खेती के साथ-साथ कुछ अन्य चीजें जोड़कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें।

इन सबके बीच ही सरकार की तरफ से किसानों को खेती के साथ-साथ बाकी मल्टीटास्किंग (Multitasking) काम करने की सलाह दी जाती है। ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट (Food Processing Unit) को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा वैल्यू एडिशन उत्पादन की प्रोसेसिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग में है। इसी आधार पर राज्य सरकारें अब किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में भी भरपूर मदद दे रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसी ही एक पहल की गई है और बागवानी विभाग किसानों की इस मुद्दे में मदद कर रहा है। किसान सुभाष सिंह भी बागवानी विभाग की सहायता से फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले किसानों में शामिल हैं।

## सुभाष सिंह को बागवानी विभाग से मिला सहयोग

हरियाणा के एक सामान्य से किसान सुभाष सिंह ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद फैसला लिया कि वह खेतीबाड़ी से जुड़कर ही अपनी आमदनी कम आने वाले हैं। पहले से ही उनके पिता फलों की बागवानी करते आ रहे थे और उन्होंने भी इसी क्षेत्र में अपना हुनर आजमाने की कोशिश की है। अपने पिता के फलों की बागवानी को काम को आगे बढ़ते हुए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई। साल 2003 में यह बिजनेस लगाने के बाद काफी समस्याएं आईं। लेकिन इस काम में बागवानी विभाग का सहयोग मिला और किसान सुभाष ने अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए लोन लिया। इस प्रोसेस में बागवानी विभाग ने भी 25 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया।

## मार्केटिंग के लिए बनाए खुद के स्टोर

आज के समय में सुभाष सिंह फलों की बागवानी तो कर ही रहे हैं, इसके साथ-साथ वह फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। इनकी इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 40 से 50 तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं।

साथ ही, गांव के करीब 20 से 25 लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिल रहा है। इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए सुभाष जी ने अपने 3 स्टोर भी बनाए हैं। इसके अलावा, खादी-ग्राम उद्योग विभाग को भी कुछ प्रोडक्ट्स (Product) दिए जाते हैं।

अपने अनुभव से सुभाष सिंह किसानों को यह बताना चाहते हैं, कि किसान अगर अपनी उपज का अच्छा दाम हासिल करना चाहते हैं। तो उन्हें अपने किसानों के व्यवसाय के साथ-साथ कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर करना होगा। खेती के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस बेहद आसानी से हो जाता है और यह बहुत फायदा भी देता है। ये किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मददगार है।

## किस योजना के तहत मिलेगा लाभ

देश में उद्यमिता (Entrepreneurship) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बीच किसानों को भी खेती के साथ-साथ एग्री बिजनेस से जोड़ा जा रहा है, ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सकें, अपनी उपज को बेहतर दाम पर बेचकर अपनी आय बढ़ा सकें।

इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना भी चलाई है। जिसके तहत फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई सभी तरह की जरूरतें जैसे खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण यानी फल, सब्जी, मसाले, फूल और अनाजों की प्रोसेसिंग, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज आदि स्थापित करने के लिए 35 फीसदी तक अनुदान दिया जाता है।

सरकार ने इस योजना की पात्रता के लिए अलग-अलग तरह के नियम बनाए हैं। अगर आप इन सभी नियम के अनुसार योग्य हैं तो आपको सरकार की तरफ से 10 लाख की आर्थिक मदद मिल सकती है। इस काम के लिए नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थाएं भी सस्ती दरों पर लोन की सुविधा देती हैं।





## जनवरी के महीने में कुछ सावधानी बरतते हुए किसान अपने गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं डबल

देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यह सभी के लिए इस समस्या का कारण बनी हुई है। उत्तर भारत में ठंड के हालात बहुत बुरे हैं और बहुत सी जगह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है। ऐसे में किसानों ने जो रबी की फसल उगाई थी उसका उत्पादन चरम सीमा पर है।

गेहूं का उत्पादन अक्टूबर के महीने में किया जाता है और मार्च और अप्रैल के बीच की कटाई शुरू कर दी जाती है। ऐसे में जनवरी का महीना इस फसल के लिए बहुत ज्यादा अहम माना गया है। अगर जनवरी के महीने में स्पेशल पर ध्यान ना दिया जाए तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद भी हो सकती है। साथ ही, अगर किसान थोड़ा सा ध्यान देते हुए इस महीने में फसल की देखभाल करें तो अपने उत्पादन को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं।

गेहूं की फसल की अच्छी उपज के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है, कि गेहूं के साथ पैदा हुई खरपतवार फसल को नुकसान पहुंचाती है। इससे बचाव जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब बिहार के विशेषज्ञों ने सलाह दी है, कि जरा सी सूझबूझ से जनवरी को खेती के लिहाज से कमाई का महीना बनाया जा सकता है। किसान जनवरी के महीने में अपनी फसल को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए सही रख सकते हैं।

1. कृषि विभाग के एक्सपर्ट का कहना है, कि गेहूं की बुवाई पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में इस महीने में फसल को खरपतवार से बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के बाद चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पैदा हो जाते हैं। जो फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे बचाव के लिए 2.4-डी सोडियम साल्ट 80 प्रतिशत का 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। छिड़काव 25-30 दिनों में कर देना चाहिए।

2. अगर आपको खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं दिख रहे हैं। आप के खेत में सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं, तो आप आइसोप्रोपेटुरॉन 50 प्रतिशत का 2 किलोग्राम या 75 प्रतिशत का, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब छिड़काव करें। यह छिड़काव फ्लैट फैन नोजलवारी स्पे मशीन से करें तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।

3. छेद में तना करने वाले कीट भी गेहूं की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर समय रहते इस कीट का इलाज न किया जाए तो यह पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। इस तना छेदक कीट से छुटकारा पाने के लिए 10 फेरोमीन ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाना चाहिए। यदि अधिक जरूरत है, तो डायमथोपेट 30 प्रतिशत ई.सी 750 का पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए।

## देश के कुछ राज्यों में बढ़ गई है गेहूं की बुवाई

कृषि मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों की बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में राजस्थान राज्य में गेहूं की बुवाई सबसे ज्यादा की गई है। अगर जगह के हिसाब से बात की जाए तो लगभग ढाई लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बुवाई की गई है। राजस्थान के बाद दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का आता है और यहां पर लगभग दो लाख हेक्टेयर जमीन पर गेहूं की फसल बोई जा चुकी है। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर और असम में अधिक गेहूं की बुवाई की गई है। इस बार के गेहूं बुवाई के आंकड़े देखकर केंद्र सरकार खुश है। इस साल गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना जताई जा रही है। किसान अगर इस महीने में जरा सा ध्यान देते हैं, तो अपना उत्पादन और आमदनी दोनों ही पिछले साल के मुकाबले बढ़ाई जा सकती है।



## तमिल नाडु राज्य के चेन्नई जनपद के मौसम से जुड़ी जानकारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चेन्नई के लिए जारी जिला पूर्वानुमान के अनुसार जिले में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 28.0-29.0 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान लगभग 19.0-20.0 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। सुबह सापेक्षिक आर्द्रता के आसपास रहने की उम्मीद है। 80-90 प्रतिशत और शाम को सापेक्षिक आर्द्रता 50 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है। पवन की गति लगभग 04-12 किमी प्रति घंटा रहने की उम्मीद है और हवा की दिशा पूर्व से होगी।

### एसएमएस सलाह:

1. पहले दिन से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में तक शुष्क मौसम रहने की संभावना है।
2. पशु औषधालयों में सभी शनिवारों को कुक्कुट के लिए नियमित टीकाकरण (आरडीवीके) किया जाता है। इसलिए किसानों को तदनुसार सलाह दी जाती है।

### पशुधन संबंधित सलाह

1. खराब मौसम तक पशुओं को सुबह जल्दी चरने नहीं देना चाहिए।
2. पीने के पानी को शरीर के तापमान तक गर्म करना चाहिए। ताकि शरीर के तापमान में गिरावट से बचा जा सके।
3. खलिहान के फर्श को गर्माहट देने के लिए पुआल/लकड़ी की छीलन/सूखी सामग्री से बिछाना चाहिए और जानवरों को आराम।
4. प्रसव के करीब आने वाले गर्भवती पशुओं को अलग से साफ सूखे आश्रय में रखा जाना चाहिए और जरूरी भी है। साइड की दीवारों को कवर करके क्लोड स्ट्रेस से सुरक्षित रहें।
5. युवा बछड़े के शेड में पर्याप्त बिस्तर होना चाहिए। ताकि क्लोड तनाव को रोका जा सके जो बहुत हानिकारक है। युवा स्टॉक कुल।



## हरा मोना उगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है 50% सब्सिडी

आजकल बांस का इस्तेमाल फर्नीचर, चटाइयां, टोकरियां, बर्तन, सजावटी सामान, जाल, मकान और खिलौने जैसे तमाम प्रोडक्ट बनाने में किया जा रहा है। बांस एक कमर्शियल क्रॉप है और इसे प्लास्टिक की जगह आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे इको फ्रेंडली माना गया है।

भारत के साथ-साथ बाकी देशों में भी बांस से बने हुए प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा मांग बढ़ रही है। इसी डिमांड को देखते हुए बहुत से राज्यों में बांस आधारित छोटे छोटे और बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं और सरकार द्वारा बांस की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की बात करें तो उनके द्वारा भी नेशनल बैंबू मिशन चलाया गया है।

इसी कदम की और एक नई पहल छत्तीसगढ़ सरकार ने भी की है और यह सरकार बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए 50% तक सब्सिडी दे रही है। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के किसान हैं तो आप सिर्फ आधे खर्च में बांस की खेती कर सकते हैं और बाकी आधा खर्चा पूरी तरह से सरकार द्वारा उठाया जाएगा।

### बांस की खेती के लिए सब्सिडी

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत राज्य में बांस की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अगर कोई भी किसान इस स्कीम के तहत आवेदन देता है तो उसे सरकार की तरफ से 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। शर्त यह है, कि आपको टिशू कल्चर से बांस की खेती करनी होगी, जिसमें उद्यानिकी, वन विभाग और कृषि विभाग मिलकर किसानों की मदद करेंगे।

टिशू कल्चर से बांस की खेती करने वाले किसानों को इस योजना के तहत पैसा तीन किस्तों में दिया जाएगा। पहले साल में पहली किस्त 11,500 रुपये की, दूसरे साल में 7,000 रुपये और तीसरे साल में भी 7,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है।

इस तरह एक एकड़ खेती की इकाई लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी की दर से अनुमानित 25,500 रुपये का अनुदान किसानों को मिल जाता है। किसान चाहें तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का लाभ लेकर अधिकतम 5 एकड़ जमीन पर बांस की खेती कर सकते हैं।

### फसल के लिए पौधा खरीदने और बेचने का क्या है प्रबंध?

किसानों के उत्पादन को अच्छा करने के मकसद से, बिहार सरकार द्वारा शेड फार्मिंग तकनीक को अपनाने के लिए शेड नेट पर 75% तक का अनुदान दिया जाना बेहद सराहनीय कार्य है। इससे किसानों की फसल का उत्पादन किसी भी प्राकृतिक आपदा अथवा रोग इत्यादि से प्रभावित नहीं होगा। किसानों को बेहतर उत्पादन करने से काफी सहूलियत मिलेगी। इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति एवं जीवनशैली में भी बेहतर सुधार आएगा। अगर आपके मन में भी इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर चिंता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत किसानों को बांस की खेती के लिए एकदम निशुल्क पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिसकी रोपाई, सिंचाई और फेंसिंग अपने खर्च पर करनी होगी।

बांस की रोपाई के 3 साल बाद अनुदान की राशि जीवित पौधों के हिसाब से कैल्कुलेट करके किसान को दे दी जाएगी। इसके अलावा, खेती से जुड़े बाकी कामों में उद्यानिकी, वन विभाग और कृषि विभाग भी किसानों का सहयोग करेंगे।

### कैसे कर सकते हैं आवेदन

छत्तीसगढ़ वन विभाग के ऑफिशल पोर्टल पर जाकर आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। <http://www.cgforest.com/> अगर आप इस खेती के लिए सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। तो वन विभाग के कार्यालय में जाकर आपको एक आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। जिसमें आपको अपनी, आधार, कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, खेत का खसरा-खतौनी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स देना अनिवार्य है।



## इस राज्य में 50 प्रतिशत अनुदान पर मिल रहे ट्रैक्टर जल्द आवेदन करें

हरियाणा राज्य सरकार किसानों के लिए अहम कार्य कर रही है। प्रदेश में किसानों को 50% अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध करा रही है। जिसका लाभ लेने के लिए किसानों को 20 जनवरी तक ड्रा रजिस्ट्रेशन हेतु <https://agriharyana.gov.in/> पर ऑनलाइन 10,000 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा।

आजकल कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण एवं आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्योंकि अधिकांश खेती किसानों से जुड़े कामों में किसानों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और समय भी अधिक लगता है। मशीनों के उपयोग से इन दोनों समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। दरअसल, मशीनों के प्रयोग से समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखकर ट्रैक्टरों पर अनुदान देने की पहल की है। इसकी मुख्य वजह यह है कि अधिकांश कृषि यंत्र ट्रैक्टर के माध्यम से संचालित किये जाते हैं। साथ ही, ट्रैक्टर की मदद से किसान कृषि कार्यों सहित के उत्पादन को बाजार में ले जाने के लिए भी मदद मिलेगी।

ट्रैक्टर का मूल्य काफी महंगा होने की वजह से हर किसान इसको खरीदने के लिए सक्षम नहीं होता है। हालांकि, किसान हित में चलाई गई योजनाओं ने इस कार्य को काफी सुगम बना दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं के तहत ट्रैक्टर खरीदने हेतु कर्ज एवं अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी क्रम में फिलहाल हरियाणा सरकार व अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी किसानों को ट्रैक्टर खरीदने हेतु सहायता की जा रही है। हरियाणा सरकार किसानों को 50% अनुदान की सहायता करके किसानों को ट्रैक्टर मुहैया करा रही है।

### हरियाणा सरकार अनुदान पर उपलब्ध करा रही ट्रैक्टर

आपको बता दें कि हरियाणा कृषि विभाग की तरफ से पानीपत जनपद के कृषकों को 30 ट्रैक्टर सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ट्रैक्टर पर दिए जा रहे अनुदान की अधिकतम राशि 3 लाख रुपये मतलब 50% फीसद तय की गई है। जो भी किसान अनुदान पर ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो वह 20 जनवरी तक अपना ड्रा पंजीयन सुनिश्चित कर लें।

इसी संदर्भ में जिला उपायुक्त ललित सिवाच का कहना है, कि प्रमाणित किसानों हेतु ड्रा रजिस्ट्रेशन का शुल्क 10,000 रुपये तय किया गया है। जिसे <https://agriharyana.gov.in/> पर ऑनलाइन तौर पर जमा कराना होगा। यदि किसानों के द्वारा आवेदन करने के उपरांत इस शुल्क को पोर्टल के जरिए से जमा नहीं करवाया, ऐसी स्थिति में उनका आवेदन रोक लिया जाएगा। साथ ही, जो किसान शुल्क जमा कर देंगे, उनका ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से जिला स्तर की समिति चयन करेगी।

किसान इस योजना का कैसे फायदा उठा सकते हैं

इस योजना के सन्दर्भ में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक अभियंता का कहना है, कि चयन के बाद किसान को अनुमोदित निर्माता अथवा डीलर से स्वयं की रुचिनुसार ट्रैक्टर के मॉडल की खरीद लें। उसके बाद अनुदान की निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त शेष लागत अनुमोदित वितरक के खाते में ई-वाउचर सहित जमा करानी होगी।

इसी मध्य निर्माता वितरक को भी किसान की विस्तृत जानकारी, बैंक का विवरण, ट्रैक्टर का मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ई-मेल के माध्यम से सब्सिडी ई-वाउचर हेतु आवेदन करना होगा।

अनुदान का लाभ लेने के लिए निर्धारित शुल्क की अंतिम तिथि

हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर पर 50% अनुदान पाने हेतु 16 जनवरी तक शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा कृषकों हेतु 55 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। आपको यह भी बता दें, कि इस योजना का फायदा केवल अनुसूचित जाति के कृषकों को ही मिल पाएगा। जो एस.बी. 89 योजना के तहत 35hp मॉडल के ट्रैक्टर हेतु तय नियम व पात्रता के अनुरूप आवेदन किया जा सकता है।





## किसान परिवारों को बिना हानिकारक उर्वरक के खेती करना सिखाएगी यह सरकार, जाने क्या है प्लान

आजकल हर कोई अपनी सेहत को लेकर बेहद जागरूक है और ऐसे में सभी लोग इस तरह की चीजें खाना चाहते हैं। जिसमें केमिकल या फिर किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल ना किया गया हो। इन सब बातों का ही ध्यान रखते हुए हिमाचल प्रदेश में सरकार ने किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर (Chemical Fertilizer) और कीटनाशक आदि के बिना खेती करने की सलाह दी है। योजना के तहत प्रदेश सरकार किसानों को बिना केमिकल उर्वरक और कीटनाशक खेती करना सीखा रही है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की है। जिसमें राज्य सरकार प्रदेश में कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर (Chemical Fertilizer) के प्रयोग को एकदम खत्म करने का बारे में सोच रही है। हाल ही में आई खबर में पता चला है, कि हिमाचल प्रदेश राज्य के कृषि सचिव राकेश कंवर ने इस पूरी योजना की समीक्षा की है। इस समीक्षा के अनुसार साल 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य का 83 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। बाकी के बचे हुए लक्ष्य को भी जल्दी ही पूरा करने की संभावना है।

इस आर्टिकल में हम ये जाने की कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना क्या है। हिमाचल की सरकार इसको ग्राउंड लेवल पर उतारने के लिए क्या काम कर रही है?

### क्या है प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना ?

जैसा कि पहले ही बताया गया है, कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर (Chemical Fertilizer) और कीटनाशकों के इस्तेमाल को खत्म करना है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 3226 में से 2934 पंचायतों के 72,193 किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के बारे में पूरी तरह से जानकारी देते हुए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों को फर्टिलाइजर और कीटनाशक के उपयोग के नुकसान के बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरह से दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार के आर्थिक रूप से भी मदद भी उपलब्ध कराएगी।

### राज्य के किसान परिवारों को लाया जाएगा एक साथ

हिमाचल प्रदेश की सरकार इस योजना के तहत लगभग 10 लाख किसान परिवारों को एक साथ लेकर आएगी और उन्हें इस योजना से जोड़ने का प्रयत्न करेगी। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है, कि सरकार का प्रयास है, कि कोई भी किसान प्रदेश में केमिकल फर्टिलाइजर (Chemical Fertilizer) और कीटनाशक का प्रयोग न करें। केमिकल फर्टिलाइजर (Chemical Fertilizer) इस्तेमाल करने का नुकसान यह होता है, कि जमीन की उर्वरक क्षमता क्षीण होती है। राज्य सरकार योजना के तहत प्रदेश के हर किसान को जोड़ेगी। फिलहाल दस लाख किसानों का इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

### किसानों को क्या होगा योजना का फायदा

यह योजना पर्यावरण के लिए तो अच्छी है ही साथ ही है किसानों के लिए भी बेहद लाभकारी साबित होने वाली है। यह प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी और आने वाले समय में उन्हें इस तरह की खेती से अच्छा खासा मुनाफा होने की भी संभावना है।





## महिला किसान केवल एक क्लिक करते हुए मुफ्त बीज वितरण योजना का फायदा कैसे उठाए

हम सभी को लगता है, कि खेती करना एक आसान काम है। लेकिन ऐसा नहीं है, कृषि में एक बार फसल लगा लेने के बाद उत्पादन लाने के लिए बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इस काम में किसानों की मेहनत-मजदूरी से लेकर मिट्टी, मौसम, तकनीक, विधि, प्रबंधन, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी, मेहनत, निगरानी, सिंचाई या फिर कटाई करने का तरीका। इन सभी कामों को बेहतर ढंग से करके आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस बीच जो बेहद जरूरी है। वह है कृषि उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बीज। अगर बीज नहीं होगा तो फसल उत्पादन करना संभव ही नहीं है।

कृषि एक्सपर्ट की मानें तो जिस तरह से एक अच्छा घर बनाने के लिए नीम की मजबूती मायने रखती है। ठीक उसी तरह एक अच्छी फसल के लिए स्वस्थ और उन्नत बीज होना बेहद जरूरी है। बीज की क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी। उत्पादन भी उतना ही अच्छा होता है।

साथ ही अगर किसान अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं उग आते हैं, तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। बाजार में देसी और हाइब्रिड बीज अच्छे दामों पर मिलते हैं। कृषि विशेषज्ञ और सरकार भी इन बीजों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाती है। इन सबके बीच राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही कमाल की पहल की है, जिसमें खेती के लिए तमाम फसलों के बीज सरकार द्वारा मुफ्त बांटे जा रहे हैं।

यह काम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किया जाता है। इस स्कीम के जरिए राज्य की सरकार महिला सशक्तिकरण का काम भी कर रही है। यानी इस स्कीम का लाभ सिर्फ महिला किसान या किसान परिवारों की महिला सदस्यों को दिया जाता है। ताकि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर बना सकें।

### मुफ्त बीज वितरण योजना

राजस्थान सरकारों ने किसानों की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना चलाई है। जिसके तहत कृषि से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों के जरिए किसानों को लाभ दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत राजस्थान मिलिट्स प्रोत्साहन मिशन और राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण कार्यक्रम भी शामिल है। जिसके तहत राज्य की महिला किसानों या किसान परिवारों की महिला सदस्यों को दलहन और मोटे अनाजों के बीजों की मिनीकिट दी जाती है। ताकि वो इन बीजों से खेती करके आत्मनिर्भर बन सके। इस स्कीम के तहत प्रमुख तौर पर मूंग, मोठ, उड़द, सरसों, ज्वार, जई, बाजरा समेत कई फसल के बीजों की मिनी किट निशुल्क दी जाती है।

### कौन उठा सकता है योजना के तहत लाभ

राजस्थान में महिला किसानों और किसान परिवारों की महिला सदस्यों को बीजों की एक मिनीकिट मुफ्त में वितरित की जा रही है। इस योजना के तहत प्राथमिकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली महिला किसान को दी गई है। लेकिन महिला के पिता, पति, ससुर के नाम से जमीन हो, या किसान परिवार की सदस्य हो, तब भी आवेदन करने पर सरकार की तरफ से बीज की मिनीकिट उपलब्ध करवाई जाती है।

### कैसे मिलेंगे योजना के तहत मुफ्त बीज

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला किसानों को आर्थिक बल देना है। इस योजना का लाभ रबी और खरीफ सीजन की शुरुआत में दिया जाता है। जिले में कृषि विभाग के अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक महिलाओं को बीजों की मिनीकिट मुफ्त में वितरित करते हैं। इसके लिए महिला को अपना जन आधार कार्ड दिखाना होता है।

अगर आप भी राजस्थान में रहती हैं और महिला किसान हैं या फिर किसान परिवार की महिला हैं। आप अपने जिले में ही स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर बैठे जानकारी लेना चाहते हैं। सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जो है 1800-180-1551 यहां पर कॉल करते हुए आप आगामी बीज वितरण कार्यक्रम के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं।

### महिला किसानों को मिला आर्थिक संबल

किसी राज्य में महिला किसानों के लिए चलाई जा रही सबसे खास योजनाओं में एक राजस्थान सरकार की बीजों की निशुल्क मिनीकिट वितरण योजना भी है। इस स्कीम का लाभ लेने वाली महिला किसानों को कहना है, कि कई बार खेती के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी और खेती करने में परेशानी होती थी। लेकिन आज सरकार की योजना से आर्थिक संबल मिलने के बाद खाली खेतों भी हरियाली से लहलहा उठे हैं।







## मसाला उत्पादन कर मालामाल हो सकते हैं, राजस्थान के किसान देखें क्या है सरकार की नई स्कीम

पुराने समय से ही भारत मसालों का देश रहा है। यहां बहुत तरह के मसाले मिलते हैं। भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी मसालों की डिमांड बढ़ी है। मसालों की डिमांड बढ़ने से अब किसान इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। अगर मुनाफे की बात की जाए तो यह खेती आपको काफी फायदा दे सकती है। आप चाहे तो अपनी जमीन को मसालों के बागान में बदल सकते हैं।

राजस्थान सरकार का उद्यानिकी विभाग की राज्य में मसालों की खेती और इसके क्षेत्र विस्तार के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ लेकर कम से कम खर्च करके 4 हेक्टेयर खेत में मसालों का बंपर उत्पादन ले सकते हैं।

### कितना मिलेगा अनुदान

रिपोर्ट की मानें तो राजस्थान सरकार मसालों का उत्पादन करने वाले किसानों को ना सिर्फ आर्थिक सहायता दे रही है। बल्कि वह उन्हें तकनीकी सहयोग भी मुहैया करवा रही है। इसमें आपको खेती के बारे में सभी तरह की जानकारी पूरी तरह से दी जाएगी। इस स्कीम के नियमानुसार, जिन किसानों ने अभी तक मसालों की खेती पर अनुदान योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा। आवेदन की बात की जाए तो कोई भी किसान जिसके पास ज्यादा से ज्यादा 4 हेक्टेयर और कम से कम आधा हेक्टेयर खेत है। वह इस स्कीम के तहत अनुदान ले सकता है। दी जाने वाली राशि प्रति हेक्टेयर 13,750 रुपये निर्धारित की गई है, जिस पर 40% सब्सिडी यानी 5,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिल सकता है।

इतना ही नहीं, मसालों की खेती के लिए किसानों को विभाग की तरफ से पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का लीफलेट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। बीज, पोषक तत्व, कीटनाशक आदि भी अनुदानित लागत पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए [dipr.rajasthan.gov.in](http://dipr.rajasthan.gov.in) पर विस्तार से पढ़ सकते हैं।

### इन जिलों में मिलेगा लाभ

स्कीम के तहत राजस्थान उद्यानिकी विभाग ने 25 जिलों का चुनाव किया है। वह जिले इस प्रकार से हैं, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, बारां, करौली शामिल है। जहां के किसान मसालों की खेती पर अनुदान का लाभ ले सकते हैं।

### कैसे करें आवेदन

मसालों की खेती या मसालों का नया क्षेत्र विस्तार करने के लिए अपने नजदीकी जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क कर सकते हैं। इस स्कीम में आवेदन करने के लिए किसान के पास खुद की खेती योग्य जमीन, खेत की जमाबंदी, जन आधार कार्ड, बिजली का बिल, बैंक पासबुक की कॉपी और राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन अगर आपके पास सभी डाक्यूमेंट्स हैं तो आप अपने नजदीकी ई-मिल केंद्र पर जा सकते हैं और चाहे तो ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं।

## फसलों के साथ पेड़ों का भी होगा अब बीमा, देखभाल के लिए सरकार से मिलेगी सब्सिडी

आज के जीवन में किसानों के लिए पेड़ों का महत्व बढ़ता जा रहा है। इनसे न केवल लोगों को ऑक्सीजन (Oxygen) मिलती है बल्कि इन दिनों पेड़ किसानों के लिए कमाई का एक मुख्य साधन बनते जा रहे हैं। पेड़ों को लगाकर किसान भाई फल, फूल, औषधि, रबड़, तेल, चंदन, पशु चारा और लकड़ी का जबरदस्त उत्पादन कर रहे हैं और जमकर पैसा कमा रहे हैं। कई किसान अपने खेतों में विविधता पूर्ण तरीके से खेत में फसल लगाते हैं। किसान अपने खेतों में तो खेती करते हैं लेकिन खेत की मेड़ों में फलदार यह औषधीय पेड़ लगा देते हैं, जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी होती है। अगर आज के युग की बात करें तो किसान अपने खेत की मेड़ों में पोपलर, महोगनी, सागवान, बबूल के पेड़ भी लगा रहे हैं। इन पेड़ों से किसान लड़की का उत्पादन करते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं।

किसानों की इस प्रकार की खेती पर अब सरकार सहायता करने जा रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को पेड़ों का बीमा करवाने की सुविधा देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार नई एग्री फॉरेस्ट्री पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। इससे किसानों को पेड़ों के बीमा का अलावा अन्य तरह के फायदे होंगे।

यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस राज्य में कृषि एक मुख्य व्यवसाय है। जिससे प्रदेश की ज्यादातर जनता जुड़ी हुई है। यहां पर बागवानी, औषधी, मसाला, सब्जी, फल और पेड़ों से लेकर घास तक की खेती होती है। इन फसलों पर मौसम की वजह से या जंगली जानवरों और कीटों के प्रकोप की वजह से नुकसान भी होता है। जिससे फसलों के हुए घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा करवाती है। इससे किसान फसल में होने वाले आर्थिक नुकसान से बच जाते हैं।





मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश की सरकार हर किसान के खेत में लगे पेड़ों का नई कृषि वानिकी नीति के तहत बीमा करवाएगी। जिससे यदि किसी भी प्रकार के प्राकृतिक नुकसान के कारण किसानों के पेड़ों को क्षति पहुंचती है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनियों के द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही इस नई कृषि वानिकी नीति के तहत पौधों की रोपाई और पेड़ों से मिले उत्पादों की मार्केटिंग में भी सरकार के द्वारा किसानों की मदद की जाएगी।

## पेड़ों की खेती के लिए भी मिलेगी सब्सिडी

आजकल देश में बढ़ती जनसंख्या और उद्योगों के कारण बाजार में लड़की की मांग तेजी से बढ़ी है। इसको देखते हुए कृषि वानिकी नीति के तहत सरकार एक नया प्रावधान जोड़ने की तैयारी में है। इसके तहत वन विभाग किसानों को पौधे मुहैया करवाएगा। जिसमें व्यावसायिक महत्व वाले पौधे भी मुहैया करवाए जाएंगे। इन पेड़ों को अपने खेतों में लगाकर किसान भाई आसानी से इमारती लकड़ी के पेड़, फूड प्रोसेसिंग के लिए आंवला जैसे पेड़, जामुन और आम सरीखे फलदार पेड़, औषधीय पौधे और अन्य वानस्पतिक किस्मों के पेड़ लगा सकते हैं। जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी होगी।

## पेड़ों से मिलने वाले उत्पादों की मार्केटिंग में सहयोग करेगी सरकार

उत्तर प्रदेश की सरकार नई कृषि वानिकी नीति के तहत पेड़ों के बीमा, उत्पादन के साथ-साथ उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की मार्केटिंग में भी सहयोग करने वाली है। इसके तहत किसानों का उद्योगों एक साथ समन्वय स्थापित करवाया जाएगा ताकि किसानों को पेड़ों की लकड़ी या दूसरी उपज बेचने के लिए बाजारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। इसके लिए प्रदेश में क्लस्टरों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही सरकार महंगे और कमर्शियल पेड़ों की देखभाल के लिए किसानों को सब्सिडी भी प्रदान करेगी ताकि किसानों के ऊपर पेड़ों की बागवानी का खर्चा भारी न पड़े।

## सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट ने पहले लकड़ी आधारित उद्योगों को लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा रखी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हटा दिया है। अब किसान बिना किसी चिंता के पेड़ों को अपने खेतों में लगा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से किसानों के साथ-साथ लकड़ी कारोबार से जुड़े दूसरे हितग्राहियों को भी भारी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार भी आगे आई है और सरकार आगामी कैबिनेट मीटिंग में कृषि वानिकी नीति पर आधारित ड्राफ्ट तैयार करके कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है।



## बाजार में मिलावटखोर लाल मिर्च में कट रहे मिलावट ऐसे करें मिलावटयुक्त मिर्च की जाँच

आज हम आपको लाल मिर्च के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप यह पहचान सकें कि कौन सी मिर्च शुद्ध है और कौन सी मिटावती। क्योंकि लाल मिर्च को अच्छी तरह जाँच परखने के उपरांत ही प्रयोग करना चाहिए। कुछ मिलावट खोर लाल मिर्च में डाई अथवा नकली लाल रंग का मिश्रण करके बेचते हैं। जो कि आपकी सेहत को काफी प्रभावित करता है। बहुत सारे तरीकों से लाल मिर्च की शुद्धता और इसकी गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। खाने को स्वादिष्ट बनाने में लाल मिर्च की अपनी अहम भूमिका होती है।

लाल मिर्च के तड़के के बिना सब्जी में मजा नहीं आता है, भारत में रहने वाले लोग बिना तड़का लगाए सब्जी चाव से नहीं खाते हैं। इसलिए लाल मिर्च भारतीय भोजन के व्यंजनों की जान मानी जाती है। इतना ही नहीं देसी लाल मिर्च के तीखेपन का चस्का वर्तमान में विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इसलिए आजकल लालमिर्च विदेश में भी खूब निर्यात होने वाले मसालों में लाल मिर्च का नाम भी शामिल है। अत्यधिक मांग होने की वजह से बाजार में लाल मिर्च की आपूर्ति नहीं हो पाती है। जिसका व्यापारी गलत लाभ उठाते हैं एवं लाल मिर्च के अंदर डाई, ईट का पाउडर, गेरुआ, लाल रंग इत्यादि का मिश्रण कर देते हैं।

जो कि एक कानूनन अपराध होता है, परंतु इसके अलावा भी लाल मिर्च में मिलावट होने की खबर सामने आती रहती है। अगर आप स्वयं तथा स्वयं के परिजनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो लाल मिर्च को उपयोग में लाने से पूर्व उसकी शुद्धता एवं गुणवत्ता की जाँच पड़ताल अवश्य कर लें। क्योंकि अगर आपने भूल से भी नकली लाल मिर्च का उपभोग किया तो आपके पेट से लेकर आँतों तक की स्वास्थ्य संबंधित बीमारियाँ आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं।

## ईट के पाउडर-गेरुआ की मिलावट की कैसे जाँच करें

मिर्च का रंग ईट-गेरुआ का रंग दोनों लाल व एक जैसे होते हैं। इसी बात का फायदा उठा कर मिलावट खोर लाल मिर्च में ऐसे हानिकारक पदार्थों की मिलावट कर देते हैं।

आप जिस मिर्च का उपयोग कर रहे हैं तो याद रहे उसमें भी यह नुकसानदायक पदार्थ मिले हो सकते हैं। इसकी जाँच पड़ताल करना काफी आसान माना जाता है। इस ईट के पाउडर-गेरुआ की मिलावट की जाँच पड़ताल के लिए एक गिलास जल लेकर उसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाकर देखें। जैसे ही आप जल में मिलाओगे आपको मिट्टी की गंध का आभास होने लगेगा जाएगा। साथ ही, पानी का रंग भी परिवर्तित होने लग जाएगा। इसका पता लगाने की एक और विधि है, जिसके अंतर्गत लाल मिर्च का पाउडर लेकर उसके ऊपर गिलास को घिसेंगे। उस स्थिति में यदि आपको किरकिरापन का आभास हो तो मान लीजिए कि लाल मिर्च में मिलावटयुक्त होने की आशंका है।

## डाई अथवा आर्टिफिशियल (Artificial) रंग की मिलावट की कैसे जाँच करें

लाल मिर्च में आमतौर पर डाई और आर्टिफिशियल रंग की मिलावट के बारे में भी बहुत सी बात सामने आएंगी। हालांकि, ब्रांडेड लाल मिर्च में इस प्रकार की खबर नहीं सुनी है। परंतु, खुले रूप से बिकने वाले लाल मिर्च पाउडर में डाई अथवा आर्टिफिशियल रंग मिले होने के अधिक होते हैं।

इसकी जाँच पड़ताल करने हेतु एक गिलास जल में एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर का उचित प्रकार से मिश्रण कर लें। अगर लाल मिर्च को बेहतर ढंग से घोला जाए एवं पानी का रंग गहरा लाल हो जाए तब जान लें कि लाल मिर्च मिलावटयुक्त है। क्योंकि लाल मिर्च को जल में नहीं घोल सकते हैं। यह जल के ऊपर भाग पर ही तैरती रहती है।

## लाल मिर्च पाउडर में स्टार्च की मिलावट का कैसे पता लगाएं

हम जब कभी भी लाल मिर्च में स्टार्च की मिलावट के बारे में सुनते हैं। उस स्थिति में हमको जागरूकता एवं सावधानी से शुद्धता की जाँच पड़ताल अवश्य करनी चाहिए। अगर आप भी खरीदकर लाए लाल मिर्च पाउडर में स्टार्च की मिलावट के बारे में पता लगाना चाहते हैं। तो इसकी जाँच करने हेतु आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर कटोरी में डालें एवं इसमें टिंचर आयोडीन अथवा आयोडीन Solution की कुछ बूँदें मिलाएं।

वर्तमान में अगर लाल मिर्च पाउडर का रंग नीला होने की स्थिति में है तो स्टार्च की मिलावट जरूर हुई है, उसको खाने के बाद ही आपका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है।

## FSSAI द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं

मिलावटयुक्त लाल मिर्च के बारे में सूचना लोगों तक मुहैया कराने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बहुत सी कोशिश में लगा रहा है। एक जागरूकता अभियान के दौरान यह व्यक्त किया गया। कैसे लाल मिर्च में चाक पाउडर, चोकर, साबुन, लाल तेल, ईट का चूरा, पुरानी और खराब मिर्च आदि मिलायी जाती है। इसको खाने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इसका सेवन करने से पूर्व लाल मिर्च की शुद्धता की जाँच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए।

## खुशखबरी: इस राज्य में आवारा पशुओं में परेशान किसानों को मिलेगी राहत

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना को स्वीकृति प्रदान करदी है। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को आवारा पशुओं द्वारा मचाई जा रही तबाही से राहत प्रदान करने हेतु 1,500 ग्राम पंचायतों में गौशाला एवं आश्रय निर्मित किए जाएंगे। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में छुट्टा घूमने वाले गौवंशों की संख्या में बढ़वार देखने को मिल रही है। इन दुधारू पशुओं से जब पशुपालकों को दूध की प्राप्ति नहीं होती तो इनको सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में यह पशु सड़कों को ही अपना घर मान लेती हैं। जिसकी वजह से आप दिन सड़क दुर्घटनाओं की खबर सुनने को मिलती हैं। साथ ही, इनके खाने के लिए चारे की कोई व्यवस्था ना होने की वजह से ये पशु खेतों में घुंसकर फसलों को नष्ट कर देते हैं। जो कि किसानों के लिए ही चुनौती उत्पन्न करती है। राजस्थान, यूपी और बिहार में आवारा गौवंशों की परेशानियों में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। इन तीनों प्रदेशों की राज्य सरकारें स्वयं के स्तर पर इस चुनौती से निपटने हेतु कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यानी राजस्थान सरकार ने भी अहम निर्णय लिया है। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ग्राम पंचायतों के अंतर्गत पशु आश्रय स्थल एवं गौशालाओं के निर्माण की घोषणा करदी है। इस कार्य को मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के चलते किया जाना है।



## गौशाला/पशु आश्रय स्थल बनाने की क्या रणनीति है

राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना को मंजूरी दे दी है। इसके प्रथम चरण में 1,500 ग्राम पंचायतों में गौशालाएँ व पशु आश्रय स्थल बनेंगे, इसके लिए 1,377 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता से पशुओं हेतु आश्रय स्थल निर्मित किए जाने हैं। जहां इनको चलाने हेतु बेहतर कार्यकारी एजेंसी (ग्राम पंचायत, स्वयं सेवी संस्था उपस्थित रहेगी। राज्य इन इन ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण हेतु एक-एक करोड़ रुपये की धनराशि का आबंटन किया जाना है। इस योजना के अनुसार, 90% फीसद धनराशि को राज्य सरकार एवं 10% फीसद धनराशि को कार्यकारी एजेंसी द्वारा वहन किया जाना है। फिलहाल, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 183.60 करोड़ रुपये के खर्च से 200 एवं वर्ष 2023-24 में 1,193.40 करोड़ रुपये के खर्च से 1,300 ग्राम पंचायतों में गौशालाएँ बनायी जा रहा है।

## किसानों को छुट्टा पशुओं से मिलेगी राहत

आवारा पशुओं की तादात में वृद्धि का सर्वाधिक नुकसान किसानों को ही तो भोगना होता है। यह आवारा पशु खेतों में जाकर के फसलों को खा जाते हैं। फसल का उत्पादन प्राप्त होने से पूर्व ही किसानों के सारा खेत पशु खाकर साफ कर देते हैं। इस प्रकार पूरे सीजन अथक प्रयास और परिश्रम करने वाले किसानों को केवल निराशा और हताशा ही प्राप्त होती है। आवारा पशुओं द्वारा बहुत बार किसानों को उस हद तक हानि हो जाती है। जिसका मुआवजा तक किसानों को मिलना काफी कठिन सा हो जाता है, जिस की वजह से आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। परंतु, अब राजस्थान के किसानों की इस परेशानी का निराकरण तो निकलेगा ही, साथ ही, छुट्टा एवं निराश्रित पशुओं को आश्रय स्थल भी मुहैया हो पाएगा।

## किसानों को छुट्टा पशुओं से मिलेगी राहत

मीडिया की खबरों के मुताबिक, वर्ष 2022-23 के अंतर्गत ही राजस्थान सरकार द्वारा अपने बजट में ग्राम पंचायतों में गौशाला एवं पशु आश्रय स्थल निर्माण एवं उनके बेहतर ढंग से संचालन हेतु की घोषणा कर दी थी। इसी दिशा में अग्रसर होकर कार्य करते हुए राजस्थान राज्य में गौशालाओं को 9 महीने तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

## इस राज्य में सबसे ज्यादा किसान कर रहे हैं आत्महत्या, जाने क्या है कारण

एक बार फसल लगाने के बाद किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूखा और बहुत ज्यादा बारिश उनमें से एक हैं। बहुत ज्यादा बारिश होने से कभी-कभी खेतों में खड़ी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। जो किसानों के ऊपर भारी कर्ज और परेशानी छोड़ देता है।

पिछले साल बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। इससे खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, ऐसे में किसान कर्ज में डूब गए। मीडिया की रिपोर्ट की मानें तो साल 2022 में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में लगभग 1000 से ज्यादा किसानों ने इन समस्याओं के चलते आत्महत्या की है। यह आंकड़े बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। कार्यालय के अधिकारियों की मानें तो इससे पिछले साल की गई आत्महत्या 887 थी जो इस साल बढ़कर 1023 हो गई हैं। किसानों की आत्महत्या एक ऐसा आंकड़ा है, जो कोई भी सरकार बढ़ाना नहीं चाहती है।

मीडिया की रिपोर्ट की मानें तो साल 2001 और साल 2010 के बीच हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इनमें से बहुत से रिपोर्ट मीडिया में दर्ज भी नहीं होती है। यह आंकड़े ना सिर्फ चौकाने वाले हैं बल्कि दुखदाई भी हैं। एक बार फसल बर्बाद हो जाने के बाद किसानों के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है। वह मौत को गले लगाना ही सबसे सही समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, इस क्षेत्र में कुछ वर्षों में सूखे जैसी स्थिति और अन्य में अत्यधिक बारिश देखी गई है, जिसने फसल उत्पादकों की कठिनाइयों को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई नेटवर्क का भी पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

## दिसंबर और जून के बीच बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं

जिला प्रशासन के सहयोग से उस्मानाबाद में किसानों के लिए एक परामर्श केंद्र चलाने वाले विनायक हेगाना ने किसान आत्महत्याओं का विश्लेषण करते हुए छोटे से छोटे स्तर पर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऊंचे लेवल पर कई तरह की नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही हैं और साथ ही जमीनी स्तर पर भी कई तरह के सुधार किए जा रहे हैं। ताकि इस तरह की घटनाओं को कम किया जा सके।

इससे पहले जुलाई और अक्टूबर के बीच सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं दर्ज की गई थी। लेकिन पैटर्न बदल गया है। उन्होंने कहा कि अब किसानों की आत्महत्या की घटनाएं दिसंबर और जून के बीच संख्या बढ़ रही हैं।

## किसानों को अपनी उपज का अच्छा रिटर्न मिलना है जरूरी

संख्या पर अंकुश लगाने की नीतियों पर हेगाना ने कहा कि इन नीतियों में खामियां ढूंढना और उन्हें बेहतर बनाना एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। साथ ही जरूरी है, कि कुछ ऐसे लोगों का समूह बनाया जा सके जो इस पर काफी एक्टिव हो कर काम करें। संपर्क किए जाने पर, महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि हालांकि किसानों के लिए कई बार कर्जमाफी हुई है। लेकिन आंकड़े (आत्महत्या के) बढ़ रहे हैं। उन्होंने मीडिया में कहा कि केवल किसानों का कर्ज माफ कर देना ही काफी नहीं है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा खासा रिटर्न मिले। जब किसान फसल लगाते हैं, तो उस पर काफी तरह का खर्चा करते हैं। अगर वह खर्चा ही ना निकाल पाए तो यह उनके लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट बन कर सामने आता है। दानवे ने बहुत ही ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे घटिया किस्म के बीज और खाद के बारे में भी बात की और इस पर चिंता व्यक्त की है। अगर किसानों को सही तरह के बीज और खाद ही नहीं मिल पाएंगे तो उत्पादन को बढ़ाना मुश्किल है।



## इस देश में प्याज की कीमतों ने आम जनता के होश उड़ा दिए हैं

प्याज बागवानी के अंतर्गत अत्यधिक खपत होने वाली सब्जी है। जिसके मूल्य में बढ़ोत्तरी होने पर लोगों पर काफी प्रभाव पड़ता है। भारत में जब भी प्याज के दाम बढ़ते हैं, तो लोगों को काफी परेशानी होने लगती है। फिलहाल फिलीपींस (Philippines) की भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि फिलीपींस में प्याज के भावों ने तबाही मचा रखी है। वहां प्याज भारतीय करेंसी की तुलना में 900 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है।

बागवानी फसलें जैसे कि भावों को संतुलन में रखना बेहद आवश्यक होता है। इनके भाव बढ़ने से आम जनता की रसोई का बजट खराब हो जाता है। साथ ही, सरकार के ऊपर भी भाव को संतुलन में लाने के लिए दबाव बनने लगता है। इस मुद्दे पर विपक्ष भी सक्रियता से सरकार को घेरता है। अगर निरंतर भावों में बढ़ोत्तरी देखने को मिले तो आम जनता भी खिलाफ में सड़कों पर उतर आती है। आजकल फिलीपींस की भी यही दसा देखने को मिल रही है। इसकी वजह यह है कि यहाँ प्याज की कीमत में बेहद ऊंचाई पकड़ली है। वहाँ के देशवासियों की हालत दूभर हो गई है। आम जनता सरकार से भावों को नियंत्रण में लाने के लिए गुहार कर रही है।

## फिलीपींस में प्याज के भाव ने लोगों को चिंतित कर दिया है

फिलीपींस में प्याज के भाव सातवें आसमान पर हैं। खबरों के मुताबिक, वहां प्याज का मूल्य 11 डॉलर पर टिकी हुई है। भारतीय करेंसी की तुलना में इसका मूल्य 900 रुपये के आसपास है। वर्तमान में भारत के बाजारों में सेब 80 से 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। इस परिस्थिति में फिलीपींस के एक किलो प्याज के भाव में 10 किलोग्राम सेब खरीदे जा सकते हैं।

## फिलीपींस मार्च तक हजारों टन प्याज आयात करेगा

वर्तमान में प्याज के बढ़ते दामों की वजह से फिलीपींस सरकार भी काफी दबाव में है। प्याज की घरेलू उपभोग की आपूर्ति के लिए जनता द्वारा सरकार से निरंतर मांग की जा रही है। फिलीपींस सरकार ने इसको गहनता से लिया है। सरकार ने घरेलू खपत सुनिश्चित करने हेतु मार्च तक तकरीबन 22,000 टन प्याज का आयात हेतु घोषणा करदी है। सरकार की घोषणा के बाद आम जनता को उम्मीद और शांति मिली है। परंतु, जनता प्याज आयात हेतु प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूर्ण करने की गुहार कर रही है।

## चीन से तस्करी से आई 153 मिलियन डॉलर की प्याज जब्त

कुछ खबरों के अनुसार फिलीपींस में चीन से प्याज की तस्करी हो रही है। तस्करी-विरोधी प्रयासों की निगरानी करने वाली समिति के प्रमुख कांग्रेस जॉय सालखेडा का कहना है, कि कृषि तस्करी को संतुलन में लाने हेतु भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। चीनी नागरिक एवं उनके सहयोगियों द्वारा की जा रही प्याज की तस्करी की अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाएगी। वर्तमान में फिलीपींस के सीमा शुल्क ब्यूरो द्वारा चीन से तस्करी करके लाई गई 153 मिलियन डॉलर की लाल व सफेद प्याज को जब्त कर लिया गया है।

## इस राज्य में यूरिया की कमी आने से किसानों में खलबली, 100 से 150 रूपए तक महंगा खरीदने को मजबूर

बिहार राज्य के किसान खाद की कमी होने की वजह से काफी चिंताग्रस्त हैं। बिहार के कृषि सचिव एन सररवाना कुमार के ने बताया है, कि राज्य को वर्तमान में खरीफ सीजन के तुलनात्मक केंद्र सरकार द्वारा 32 फीसद कम यूरिया (Urea) प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि, विगत माह में यूरिया की आपूर्ति सुचारू होने के बाद भी, रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार राज्य में जनवरी माह हेतु आवंटित 10,30,000 मीट्रिक टन यूरिया में से तकरीबन 7,00,105 मीट्रिक टन (एमटी) ही खाद मिल पाया है।

इसी वजह से बिहार को खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को समयनुसार खाद ना मिलने के कारण उनको पैदावार में कमी होने की चिंता काफी परेशान कर रही है। लेकिन, केंद्र सरकार के मुताबिक, बिहार राज्य को भी बाकी समस्त राज्यों के समरूप खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं मीडिया खबरों के अनुरूप, केंद्र सरकार द्वारा दावा करने के बाद भी प्रदेश में कृषकों को खाद की किल्लत सता रही है।

विगत वर्ष दिसंबर में आवंटित क्षमता के 97 प्रतिशत से अधिक खाद की आपूर्ति की गई थी। दरअसल, विभाग को आशा है, कि जनवरी माह में राज्य को उसका समुचित खाद प्राप्त हो सकता है। सिंचाई के दौरान उत्पन्न हुई खाद की कमी की वजह से अनाधिकृत व्यापारियों में मनमाने भाव पर खाद विक्रय किया है।

अनाधिकृत व्यापारियों ने मीके का फायदा उठाकर 50 किलो के उरिया के पैकेट को जिसका सरकारी भाव 260 रूपए है। लेकिन, खाद की कमी की स्थिति में उसी 50 किलो के उरिया के पैकेट को 350-400 रुपये के मध्य विक्रय किया जा रहा है।

## जानें पीएम किसान योजना जी 13 वीं किस्त कब तक आएगी

किसानों को पीएम किसान योजना की 13 वीं किस्त की बेहद उत्सुकता से प्रतीक्षा है। किसानों को अनुमान है, शायद इस हफ्ते उनकी 13 वीं किस्त उनके खाते में डाल दी जाएगी। केंद्र सरकार भी 13 वीं किस्त किसानों के खाते में भेजने हेतु पूर्ण व्यवस्था में लगी हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों को मिल चुकी है। किसान वर्तमान में 13 वीं किस्त की प्रतीक्षा में बैठे हैं। आखिर कब तक उनको 13 वीं किस्त मिलेगी। इस बात के लिए किसान सड़कों पर निरंतर बातचीत में लगे हुए हैं। किसानों द्वारा केंद्र सरकार से भी अनुग्रह किया जा रहा है, कि वह इसी माह में शीघ्र से शीघ्र उनके खाते में 13 वीं किस्त डाल दें।

## किसानों को कब तक 13 वीं किस्त मिल सकती है

अगर जनवरी माह में 13 वीं किस्त किसानों को कब तक मिलेगी। किसान इस विषय पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक, लोहड़ी एवं मकर संक्राति के त्यौहार से पूर्व किस्त किसानों को मिलने की आशा की जा रही थी। परंतु, फिलहाल जो खबरें देखने को मिल रही हैं। उनके मुताबिक तो आने वाले हफ्ते में अथवा जनवरी माह के किसी भी दिन किसानों के खातों में पहुँचा दी जा सकती है। केंद्र सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, किसानों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार निर्धारित समय पर 13 वीं किस्त किसानों के खाते में भेज देगी। दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से किस्त जारी करने के संबंध में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन, इसी हफ्ते अथवा 26 जनवरी से पूर्व किसानों के खातों में उनकी 13 वीं किस्त आने की संभावना है।

## किसानों को ऑनलाइन तौर पर

इस कार्य को करना अति आवश्यक है पीएम किसान योजना की आगामी किस्त प्राप्त करने हेतु कृषकों को ई-केवाईसी होनी आवश्यक है। जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना भी बेहद आवश्यक होता है।



पंजीयन करते समय राशन कार्ड का सॉफ्ट कार्ड जमा करना होगा। आपको हार्ड कॉपी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए पीएम किसान पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट पर आपको राशन कार्ड की PDF फाइल तैयार कर अपलोड कर दें। यदि किसानों ने राशन कार्ड की कॉपी जमा नहीं की तो उस स्थिति में किसान किस्त से वंचित रह जाएंगे।

## आधार कार्ड का बैंक खाते से जुड़े रहने की स्थिति में ही मिल पायेगा लाभ

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना बहुत आवश्यक कर दिया है। बैंक से आधार कार्ड जुड़ने की स्थिति में आपकी ई-केवाईसी पूर्ण हो जाएगी। केंद्र सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, किस्त प्राप्त करने हेतु किसानों का आधार कार्ड बैंक से जुड़ा होना चाहिए। उसके उपरांत ही 13 वीं किस्त किसानों को मिल सकेगी। बता दें, कि अपात्र एवं E-KYC नहीं होने की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 12 वीं किस्त नहीं पहुँच पायी थी। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों को ई-केवाईसी कराने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिससे कि वह पीएम किसान योजनासे लाभान्वित हो सकें।

## अगर आप भी चावल में मिलावट कर उसे बेच रहे हैं तो सावधान हो जाइए

भारत में उगाए जाने वाले बासमती चावल का पूरी दुनिया में डंका बजता है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो साल 2022-23 में बासमती चावल का निर्यात 24.97 लाख टन दर्ज किया गया है। अमेरिका और यूरोप में तो भारत के बासमती चावल की डिमांड है ही इसके साथ-साथ अरब के देशों में भी भारत से बासमती चावल मंगवाए जाते हैं। यही कारण है, कि पिछले कुछ समय में ना सिर्फ भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। बल्कि हम पूरे विश्व में बहुत ही बड़े स्तर पर चावल का निर्यात भी करते हैं।

भारत की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है, कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाजार मानकों के आधार पर खरा उतरने के बाद ही बासमती चावल का निर्यात किया जाए। लेकिन आजकल बहुत से व्यापारी और चावल वितरित करने वाली कंपनियां नकली बासमती चावल बेच रही हैं। इस तरह की गड़बड़ी करते हुए अपनी नोटों से जेबें भर रहे हैं।

ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों पर अब भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने लगाम कस दी है। अगर रिपोर्ट्स की मानें तो FSSAI ने बासमती चावल की क्वालिटी और स्टैंडर्ड के लिए खास नियम तय कर दिए हैं, जिनका पालन चावल कंपनियों को करना ही होगा। ये नियम 1 अगस्त 2023 से देशभर में लागू हो जाएंगे। नियमों का पालन न किए जाने पर व्यापारियों और कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

## अब बाजार में बिकेगा केवल नेचुरल बासमती चावल

असली बासमती चावल में अपनी खुद की एक प्राकृतिक सुगंध होती है। लेकिन आजकल कई कंपनियां आर्टिफिशियल कलर और नकली पॉलिश करते हुए बासमती चावल में बाहर से एक अलग खुशबू डाल देती हैं। इस तरह के नकली चावल देशभर में बेचे जा रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने इस कुकर्म पर लगाम लगाने की ठान ली है। ऐसी कंपनियों पर लगाम कसते हुए अब भारत सरकार के बजट में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड (फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव) फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023 नोटिफाई किया गया है।

इसमें बासमती चावल के लिए खास स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं, ताकि असली बासमती की पहचान, सुगंध, रंग और बनावट के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। नए नियमों में ब्राउन बासमती, मिल्ड बासमती, पारबॉइल्ड ब्राउन बासमती और मिल्ड पारबॉइल्ड बासमती चावल को प्रमुखता से जोड़ा गया है। इन खास तरह के स्टैंडर्ड का पालन न करने पर कंपनियों के खिलाफ सरकार की तरफ से लीगल एक्शन लिया जा सकता है।

## किसे कहेंगे असली बासमती चावल

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा निर्धारित रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के अनुसार, असली बासमती चावल वही होगा, जिसमें प्राकृतिक सुगंध होगी। साथ ही, इन नियमों के तहत बासमती चावल को किसी भी तरह से आर्टिफिशियल पॉलिश नहीं किया जाएगा।

जो भी कंपनियां बासमती चावल बेच रही हैं, उन्हें पकने से पहले और पकने के बाद के चावल का आकार निर्धारित करना होगा। इसके अलावा चावल कंपनियों को बासमती चावल में नमी की मात्रा, एमाइलॉज की मात्रा, यूरिक एसिड के साथ-साथ बासमती चावल में टुकड़ों की उपस्थिति और इनकी मात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी।

## 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे नियम

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा बासमती चावल के लिए निर्धारित रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स 1 अगस्त 2023 से लागू हो जाएंगे। इन नियमों का सबसे बड़ा मकसद बासमती चावल में हो रही मिलावट को खत्म करना है। साथ ही, ग्राहकों के हितों की रक्षा देश नियम के तहत की जाएगी। यहां पर सरकार का मकसद है, कि आपके खाने की थाली में एकदम वैसे ही चावल पहुंच सके जैसा उन्हें उगाया गया है।



# औषधीय खेती

## इस पौधे के प्रयोग से गंजापन होता है दूर साथ ही चेहरे पर आयेगा नूर

प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषज्ञ प्रीतिका मजूमदार के अनुरूप ग्वारपाठे मतलब एलोवेरा (Aloe vera) अत्यंत फायदेमंद पौधा होता है। जिसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय गुण हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद भी होता है। प्रतिदिन इसका निरंतर उपयोग कर बहुत सारे रोगों व बिमारियों से निजात पा सकते हैं।

घृत कुमारी या ग्वारपाठा मतलब एलोवेरा एक ऐसा पौधा है, जिसका उपयोग बहुत सारी बिमारियों को दूर करने के साथ-साथ सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बाजार में एलोवेरा से निर्मित उत्पाद अपनी विशेष पहचान और स्थान रखते हैं। आज हम इस लेख में जानेंगे, कि कैसे और कौन-सी चीजों में यह अत्यंत लाभकारी होता है।

## ग्वारपाठा मतलब एलोवेरा से क्या-क्या लाभ होते हैं

### जली त्वचा में लाभकारी

ग्वारपाठे के पत्ते को काटकर इसके अंदर के गूदे को बाहर लेकर के यदि आप त्वचा पर दिन में करीब 23 बार इसका लेप करते हैं, तो आपकी जलन खत्म होकर शीतलता में परिवर्तित हो जाती है।

### स्किन टैनिंग के लिए लाभकारी

ग्वारपाठा स्किन टैनिंग को दूर भगाने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके छिलके को उतारने के उपरांत इसको अच्छी तरह पीसकर जले हुए शारीरिक हिस्से पर लगाने से जखम ठीक हो जाता है और जलन भी पूरी तरह खत्म हो जाती है।

### त्वचा में सौंदर्य और निखार लाए

ग्वारपाठा व एलोवेरा रंग को निखारने में काफी सहायक साबित होता है। अगर आप इसको गुलाब जल में मिश्रित कर के अपनी जांघों पर लगाते हैं, तो इससे आपको पहले से बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए आपको ग्वारपाठा यानी एलोवेरा का उपयोग विभिन्न प्रकार के सौंदर्य उत्पादों में किया जाता है। क्योंकि यह त्वचा को नमी उपलब्ध कराके उसको काफी निखार देता है।

### पिंपल दूर करने में सहायक

एलोवेरा को काटकर उसमें से निकाले गए गूदे में अगर चार भाग में दो भाग शहद में मिश्रण कर पिंपल पर लगाएं। तो, आपको अतिशीघ्र ही इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा।

### सिर सर्द करे जड़ से खत्म

सिर दर्द होने की स्थिति में ग्वारपाठे के गूदे में गेहूँ के आटे में मिश्रण कर उसके उपयोग से 2 रोटी बनाएं। रोटी बनने के बाद उसको अच्छी तरह दबाकर के देशी घी में डालें। उस रोटी का सेवन सूर्योदय से पूर्व कर लें। इसका नियमित रूप से 57 दिन तक निरंतर सेवन करेंगे तो आपका कैसा भी सिर दर्द हो बिल्कुल सही हो जाएगा।

गंजे के भी सिर पर बाल उगादे

एलोवेरा गंजापन दूर करने में भी काफी सहायक साबित होता है। आपको लाल रंग के ग्वारपाठे जिसके अंतर्गत नारंगी एवं कुछ लाल रंग के फूल होते हैं। उसके गूदे को स्प्रिट में गलाने के उपरांत सिर पर लेप लगाने से गंजे के सिर पर भी बाल आ जाते हैं। इतना ही नहीं यह बालों को काला करने में भी सहायता करता है।

जखम पर लगाएं ग्वारपाठा

एलोवेरा कुत्ते द्वारा काटने से हुए जखम को भरने में काफी अच्छा होता है। ग्वारपाठे को एक तरफ से छीलकर इसके गूदे वाले भाग में पिसे हुए सेंधानमक का छिड़काव करें। उसके बाद इसको कुत्ते द्वारा काटी गयी जगह पर लगाएं। इसका अच्छा फायदा आपको निरंतर इसके चार बार प्रयोग करने के उपरांत ही मिलेगा।

ग्वारपाठा से पिंपल होंगे दूर

आप एलोवेरा के उपयोग से भी पिंपल की समस्या से राहत पा सकते हैं। ऐसे में आप एलोवेरा को प्रभावित स्थान पर लगाएं। कुछ समय बाद अपनी त्वचा को धो लें।

## इस राज्य के किसान अब करेंगे औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती

देश की अन्य राज्य सरकारों की तरह ही जम्मू-कश्मीर की सरकार भी अपने किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। इसके तहत सरकार समय-समय पर राज्य के किसानों को सहायता उपलब्ध करवाती रहती है। इसी के साथ सरकार किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा भी करती है ताकि किसान भाई अपने पैरों पर खड़े रह पाएं। अब सरकार ने अपने प्रदेश के किसानों के हितों को देखते हुए एक मेगा प्लान तैयार किया है जिसमें किसानों को अब औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का कहना है, कि जम्मू-कश्मीर के किसान सेब, केसर और बासमती चावल के अलावा औषधीय और सुगंधित पौधों की भी खेती करेंगे, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही प्रदेश की जीडीपी में भी बढ़ोत्तरी होगी। इस प्लान के तहत जम्मू-कश्मीर की सरकार ने कहा है, कि प्रदेश में 625 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती की जाएगी। इसके साथ ही सरकार का कहना है, कि औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के साथ ही प्रदेश के किसान दूसरी अन्य फसलों की खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। जम्मू-कश्मीर राज्य के अधिकारियों का कहना है, कि औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती से प्रदेश के किसान 750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी सालाना प्राप्त कर सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा है, कि जम्मू-कश्मीर में फिलहाल बहुत कम खेती की जा रही है। जबकी यहां पर खेती की अपार संभावनाएं हैं। अटल डुल्लू ने कहा कि हिमालय के पास औषधीय और सुगंधित गुण वाले लगभग 1,123 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर किसान इस खेती पर मेहनत करें तो हर साल प्रदेश को करोड़ों रुपये का लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वैश्विक हर्बल व्यापार लगभग 120 अरब डॉलर का है और भविष्य में इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। आंकड़ों के अनुसार यह व्यापार साल 2050 तक 7,000 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर राज्य के पास इस व्यापार में अपनी जगह बनाने का अच्छा मौका है। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में औषधीय और सुगंधित पौधों का बहुत कम उत्पादन किया जा रहा है।





औषधीय और सुगंधित गुण वाली खेती के मद्देनजर अटल डुल्लू ने बुधवार को तालाब तिल्लो में एक कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का शुभारंभ किया है। इस कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 5200 मीट्रिक टन है। इसके निर्माण के लिए नाबार्ड ने ऋण उपलब्ध करवाया है, जिसे जे एंड के एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड विकसित कर रही है। यह कंपनी जम्मू-कश्मीर सरकार की एक प्रीमियम सरकारी कंपनी है।

अपर मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा है, कि इस कोल्ड स्टोरेज का सबसे ज्यादा लाभ राजौरी, पुंछ, उधमपुर, जम्मू, कटुआ, सांबा और अन्य क्षेत्रों के किसानों को होने वाला है। यहां पर ये किसान अपने ताजे फल और सब्जियां, सूखे मेवे, डेयरी उत्पाद, फूल, मांस, मछली और अन्य उत्पादों का भंडारण बेहद आसानी से कर सकेंगे। अब किसानों को बिना भाव के सस्ते दामों पर अपनी फसल बेचने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जिससे अब किसानों को पहले के मुकाबले ज्यादा फायदा होगा और किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी हो सकेगी।



**MASSEY FERGUSON**

**9500E**

**50 HP**



**आकर्षक ऑफर्स के लिए क्लिक करें**





# पशुपालन-पशुचारा

## इस प्रकार बचायें अपने पशुओं को आने वाली शीत लहर से

पाराली जलने से देश का बड़ा इलाका प्रदूषित हो रहा है। इसका दुष्प्रभाव लोगों की सेहत पर पड़ने के साथ ही, दुधारु पशुओं को भी इससे कई हानि हैं। देशभर में अधिकतर पशु लंपी रोग से प्रभावित हैं। शीघ्र ही सर्दियां भी आने वाली हैं, ऐसे में पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी बेहतर देखभाल भी आवश्यक है। सर्दियों के दिनों में ठंड के कारण ज्यादातर पशुओं को बुखार, झंझनाहट एवं कुछ केसों में मवेशियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस प्रकार की समस्त समस्याओं से पशुओं के संरक्षण के लिए किसानों एवं पशुपालकों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

## पशुओं को ठंड से बचाने हेतु इन तरीकों को अपनायें

आमतौर पर शीत लहर के चलते पशुओं की हड्डियों में कंपकंपाहट एवं टांगों में गलन होने लगती है, इससे पशुओं को बचाने के लिए जूट का बोरा पहना सकते हैं। इससे पशुओं में गर्मी बनी रहेगी।

पशुओं की बेहतर रोग प्रतिरोधी क्षमता के लिए हरा चारा एवं सूखा चारा १:३ के अनुपात में मिलाकर खिलाना बेहद आवश्यक है।

वक्त-वक्त पर पशुओं को गर्म पानी पिलायें व दलिया अथवा चरी उपयुक्त माला में खिलायें।

शीत लहर व ठंडी हवाओं से संरक्षण हेतु पशुओं को खुले में रखने की अपेक्षा छप्पर अथवा शेड का प्रयोग करें।

सर्दियों में पशुओं को हानिकारक विषाणु से बचाने के लिए धूप में टहलाना आवश्यक है।

लंपी का कहर पूर्ण रूप से रुका नहीं है, इसी वजह से समस्त दुधारु मवेशियों का टीकाकरण अति आवश्यक है।

पशुओं के आस पास साफ सफाई रखें, सर्दियों के समय विभिन्न कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो मवेशियों को बीमार कर देते हैं।

तबले, बिछावन और कपड़े को बेहतर ढंग से सूखाने के उपरांत ही प्रयोग करें। थोड़ी सी नमी होने पर पशुओं के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

पशुओं को चिकने फर्श की बजाय बोरा या बिछावन पर बैठाने की व्यवस्था करें।

पशुओं को सरसों के तेल के साथ अच्छा आहार दें एवं खल, गुड़ के साथ अन्य पौष्टिक व बेहतर आहार खिलायें।

लंपी का कहर पूर्ण रूप से रुका नहीं है, इसी वजह से समस्त दुधारु मवेशियों का टीकाकरण अति आवश्यक है।

सर्दियों में पशुओं को पाचन क्रिया खराब होने से दस्त हो जाते हैं, ऐसे में शीघ्रता बरतते हुए पशु चिकित्सक से सलाह लें। सर्दी के मौसम में पशुओं को विभिन्न रोगों से ग्रसित होने का खतरा है। खुरपका मुंहपका रोग, निमोनिया, जुकाम एवं अन्य रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में पशु विशेषज्ञ की सलाह अनुसार रोग प्रतिरोधक टीकाकरण करना अति आवश्यक है।

## कड़कनाथ पालें, लाखों में खेलें

**कड़कनाथ मुर्गी पालन-** इस दौर में कड़कनाथ (Kadakhnath, also called Kali Masi) पालना आसान हो गया है। आप कड़कनाथ पाल कर अपनी आर्थिक हालत सुधार सकते हैं, महीने में हजारों कमा सकते हैं। कहते हैं, मूँछें हों तो नत्थलाल की तरह वरना ना हो। इसे थोड़ा बदल लें तो कह सकते हैं कि मुर्गा खाना है, तो कड़कनाथ खाओ, वरना ना खाओ।

दरअसल, कड़कनाथ ने पूरे मार्केट को हिला कर रख दिया है। यह मुर्गों की एक ऐसी प्रजाति है, जिसने पूरे बिजनेस मॉडल को बदल कर रख दिया है। इसकी कीमत तो ज्यादा है ही, पर जो स्वाद है, उसका क्या कहना। आप कड़कनाथ का मीट खाएं और बकरे का मटन, मुकाबला टक्कर का रहेगा।

## कई रोगों में लाभकारी

कड़कनाथ का महत्व इसलिए ज्यादा हो चला है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने भी इसके मीट को अप्रूव किया है। कहा जाता है, कि अगर आपको हाई बीपी है, शुगर है, कमजोरी है और मन मिचलाता है, तो कड़कनाथ का मीट आपको फायदा करेगा। ऐसा कई लोगों का कहना है, कि कड़कनाथ का मीट खाने के बाद उनका बीपी, शुगर आदि कंट्रोल में रहता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो वही बता सकते हैं जो इसे खाते हैं। लेकिन, इसकी बढ़ती डिमांड यही इंगित करती है कि मुर्गों में दम है।

## धोनी भी पाल रहे हैं कड़कनाथ

मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने फार्म हाउस में कड़कनाथ रखा है। पहले 100 चूजे लाए गए थे, अब इनकी संख्या सैकड़ों में हो गई है। कड़कनाथ का स्वाद ऐसा है, कि धोनी के फार्महाउस पर लोग लाइन लगाए रहते हैं कड़कनाथ के लिए और उन्हें पता चलता है माल खत्म हो गया है। दरअसल, इसके मीट का टेस्ट ही ऐसा है।

## रेट थोड़ा ज्यादा है

कड़कनाथ का रेट थोड़ा ज्यादा है, यह प्रति मुर्गा 1000 से 1600 रुपये तक बिकता है। अमूमन एक मुर्गा 900 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक का होता है। उसी के हिसाब से इसका रेट वैरी करता है, आम तौर पर अगर आप देसी मुर्गा भी खाते हैं, तो उसका रेट 400 से 500 रुपये प्रति किलो है। वैसे, कॉकरेल आपको 300 रुपये प्रति किलो भी मिल जाएगा और बाँयलर 140 से 150 रुपये प्रति किलो पर, जो टेस्ट कड़कनाथ का है, उसका कोई जवाब नहीं।



## कैसे पहचानें कड़कनाथ को

कड़कनाथ का खून, मीट सब काला होता है, इसकी ब्रीड पूरी तरह काली है। अगर कोई कड़कनाथ कह कर आपको लाल खून वाला मुर्गा दे रहा है तो सतर्क रहें।

## कैसे करें कड़कनाथ का पालन

कड़कनाथ को पालना थोड़ा कठिन है, पहले तो आप मन बना लें कि कड़कनाथ ही पालना है। जब मन बन जाए तो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ चले जाएं, वहां इसके चूजे आपको ठीक रेट पर मिल जाएंगे। चूजों को कैसे 30 दिनों तक रखना है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। उसे बहुत ध्यान से देखें फिर, चूजा लाने के पहले ट्रेनिंग में बताए गए तरीके से ही आप पोल्ट्री फार्म बनाएं।

ध्यान रखें, कड़कनाथ की ब्रीड को खुला पसंद है, इसलिए अगर आप ठीक-ठाक जमीन वाले हैं, आपके पास खुली जमीन है तो उसे ही इस्तेमाल करें। शुरुआती निवेश अगर आप 50000 रुपये से भी करते हैं, तो काम ठीक-ठाक चल निकलेगा। इसमें चूजों का दाना-पानी आ जाएगा, बढ़ते वक्त के साथ आपको ज्यादा निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत कम इंटेस्ट रेट पर आपको आसानी से मुर्गापालन के लिए कोई भी बैंक लोन दे देगी।

विभिन्न राज्य सरकारें मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की हैं। इससे किसानों के द्वारा स्थानीय स्तर पर मुर्गी पालन (पोल्ट्री फार्मिंग, Poultry farming) या कुक्कुट पालन (kukkut paalan) का व्यवसाय पिछले एक दशक में काफी तेजी से बढ़ा है।

## मुर्गी पालन की जगह कीजिये इस पक्षी का पालन और पाएं बंपर मुनाफा

### तीतर पक्षी को पालें और पाएं कम लागत में बंपर मुनाफा

मुर्गी पालन और बत्तख पालन के बारे में हमने बहुत पहले से ही कई तरह की चीजें सुनी हैं और यह दोनों ही व्यवसाय प्रचलन में रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने तीतर पालन के बारे में सुना है?

जी हां वही तीतर (Teetar; Grey Partridge) जिसे आप बचपन में तीतर या फिर कभी कभी बटेर कहकर बुलाते थे, और साथ ही तीतर के नाम पर बचपन में हम सब ने कई मुहावरे सुने हैं, 'आधा तीतर-आधा बटेर', तीतर लड़ाना, तीतर बाज़ होना और ना जाने क्या-क्या, उस समय बड़े आश्चर्य से सोचते थे, ये तीतर किस बला का नाम है।

आज हम आपको बताने वाले हैं कि तीतर केवल मुहावरों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी आपके बहुत फायदे का हो सकता है। उस समय हो सकता है कि आपने इस पक्षी के बारे में ज्यादा सोच विचार करने के बारे में ना सोचा हो और ना ही इसके फायदों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी रखी हो। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि कबूतर जैसा दिखने वाला ये पक्षी बाकि सभी पक्षियों से बेहद अलग है और आपके लिए बहुत फायदेमंद भी है।

तीतर पक्षी का रंग भूरा काला और लाल होता है और मादा और नर दोनों ही पक्षियों की बनावट और आकार में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। तीतर में नर और मादा दोनों ही व्यवसाय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जहां पर मादा आपको बहुत ही उत्तम क्वालिटी के अंडे और चूजे दे सकती है, वहीं पर नर तीतर का मांस आजकल बाजार में बहुत प्रचलन में है।

अगर तीतर पक्षी के थोड़े से इतिहास के बारे में बात करें तो विश्व भर में तीतर के लगभग 156 किस्म देखने को मिलते हैं, जिसमें से 46 तरीके के तीतर भारत में देखने को मिल जाते हैं।

तीतर पक्षी की एक खासियत है कि वो अपना घोंसला जमीन पर ही बनाता है और उसे जंगल, झाड़ी और खेतों में रहना पसंद है। यही कारण भी है कि खेतों में कीटनाशक आदि के इस्तेमाल और बहुत ज्यादा शिकार के कारण ये पक्षी विलुप्त होता जा रहा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सरकार ने इसके शिकार पर प्रतिबंध भी लगा दिया है इसलिए ही अगर आप तीतर का पालन करना चाहते हैं तो आपको बाकायदा सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है।

आपको लग रहा होगा कि तीतर पर इतनी जानकारी ले कर हमें क्या फायदा होने वाला है। तो हम आपको बता दें कि अगर आप एक नए बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं और आप यह बिज़नेस अगर कम लागत लगाकर करना चाहते हैं, तो आपको ये सब जानकारी होना आवश्यक है।

साथ ही आप अगर मुर्गी और बत्तख पालन से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो भी तीतर पालन आपके लिए एकदम सटीक बिज़नेस है। आज के समय में तेज़ी से ये बिज़नेस लोगों को अपनी ओर खींच रहा है और आप इसे बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो शुरुआत 5-6 तीतर पाल कर ही कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं कि कैसे आप यह बिज़नेस कर मुनाफ़ा कमा सकते हैं।

### कैसे करें व्यावसायिक पालन:

बाकि पक्षी पालन की तरह ही इसके लिए आपको एक जगह लेकर सेटअप करना आवश्यक है। आप इसके लिए जाल बना सकते हैं और उसमें इन पक्षियों को रख सकते हैं। इसके अलावा तीतर को पालते समय एक बात जो ध्यान में रखनी बेहद ज़रूरी है, वो है इनकी फीडिंग मतलब कि इसके खानपान की। इनके भोजन का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि इसी आधार पर ही मादा अंडे भी देती है। लगभग 35-40 दिन में मादा अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है और ये लगभग 10-12 अंडे एक साथ दे सकती है। अगर मादा तीतर स्वस्थ है, तो अंडे और आगे चल कर चूजे भी स्वस्थ रहते हैं।

तीतर के आहार में हमें एक बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि, गर्मियों में इन्हें चिकन या बत्तख की अपेक्षा ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। साथ ही आप सूखे दाने के साथ-साथ इन्हें कुछ ना कुछ हरे पदार्थ भी खिला सकते हैं। साथ ही इस बात का खास ध्यान रखें कि आप दिन में तीन से चार बार या फिर कम से कम दो से तीन बार इन्हें दाना जरूर खिलाएं।



## तीतर के अंडे हैं पोषण से भरपूर:

जैसा कि हमने बताया कि तीतर के लिए भोजन का बहुत महत्व है इसलिए ही अगर तीतर को सही तरह से आहार दिया जाए तो अंडों के उत्पादन और क्वालिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अंडे बाकि पक्षियों के मुकाबले ज्यादा सेहतमंद माने जाते हैं और इसका कारण है कि तीतर के अंडों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल काफी मात्रा में पाये जाते हैं। प्रति ग्राम जर्दी में 15-23 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होता है।

## मांस से भी कर सकते हैं कमाई:

हो सकता है, आपने कभी तीतर के मांस के बारे में ना सुना हो लेकिन आप तीतर के मांस से भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तीतर के मांस में चिकन के मुकाबले ज्यादा पोषण पाया जाता है क्योंकि इसका मांस चिकन के मुकाबले पतला होता है। इसमें प्रोटीन और बाकी सभी मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो आजकल हेल्थ के लिए सजग लोगों की मांग है, इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम जिंक सोडियम और विटामिन B12, B6 मिलता है। औसतन देखा जाए तो 10 से 20 किलो के तीतर को आप लगभग ₹350 में बेच सकते हैं। और यहां पर अगर हम अवधि की बात करें तो लगभग हर एक तीतर पर 25 हफ्ते की अवधि में आप 300 से 350 ₹ बचा सकते हैं।

## बाजार में है तीतर के चूजों की मांग:

पेपर के मांस और अंडों की तरह ही इसके चीजों की भी मार्केट में बहुत ज्यादा मांग है। आप चाहें तो स्वस्थ चूजों को आगे चलकर मांस के लिए पाल सकते हैं और उनके पोषण के लिए आप उन्हें दूध और अंडे दे सकते हैं।

तीतर के चूजे प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसलिए बाजार में उनका बहुत ज्यादा प्रचलन है। यहां पर हमें एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, कि तीतर के चूजों में सबसे ज्यादा मौत भुखमरी के कारण होती है। इसीलिए हमें उनके खान-पान का बेहद ध्यान रखना पड़ता है और उन्हें समय-समय पर दाना और पानी देते रहने की आवश्यकता है।

## तीतर करता है खुद ही सफाई

तीतर पक्षी छोटे केंचुए और कीड़े मकोड़े खाने में सक्षम है, इससे तीतर को प्रोटीन भी मिलता है और उनकी सेहत भी बनी रहती है। इसलिए तीतर के पालन में आपको एक फायदा यह है कि इससे आपके आसपास के इलाके की सफाई भी हो जाती है। और साथ ही तीतर की सेहत पर भी इससे कोई असर नहीं पड़ता है।

## चिकन पालन से कैसे है यह सस्ता

चिकन या मुर्गी पालन से तीतर का पालन करने का व्यवसाय सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुर्गी पालन में हमें साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन तीतर पक्षी में ऐसा नहीं है, आप कम लागत पर इसका रखरखाव और सफाई कर सकते हैं। इसके पालन के लिए आपको कम जगह की जरूरत पड़ती है, साथ ही इसके पालन में आपको निवेश भी कम करना पड़ता है।

## लाइसेंस लेना है जरूरी

अगर आपने यह मन बना लिया है कि आप तीतर पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसे मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो यह बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इसे आप बिना लाइसेंस के शुरू नहीं कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, भारत सरकार ने तीतर के शिकार को प्रतिबंधित कर रखा है क्योंकि यह एक विलुप्त प्रजाति का पक्षी माना जाता है। बहुत ज्यादा शिकार और अलग-अलग तरह के दवाइयों और केमिकल के इस्तेमाल के कारण यह पक्षी विलुप्त प्रजाति में आ गया था। इसीलिए इसके संरक्षण के लिए सरकार ने लाइसेंस पद्धति का सहारा लिया है।

अगर आपने तीतर पालन के लिए सेटअप तैयार कर लिया है और अपना मन बना लिया है, तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है। साथ ही आप यह व्यवसाय करके विलुप्त होते हुए तीतर की प्रजाति को बचाने में भी अपना अहम योगदान दे सकते हैं।

इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि आजकल मार्केट में जहां आपको हर जगह मुर्गी या बतख पालन करने वाले व्यवसाय मिल जाएंगे, वहीं पर तीतर तीतर पालन एक नया व्यवसाय है। लेकिन इन दोनों ही व्यवधान से ऊपर आप यहां पर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, इसके अलावा यहां पर आपको लागत भी कम लगानी पड़ेगी। आने वाले समय में इसकी मांग और बढ़ने वाली है, जिस तरह से हम आप दिन लोगों का स्वास्थ्य के प्रति ध्यान बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और नई नई चीजों के प्रति लोगों का आकर्षण देख रहे हैं। तो जल्द ही तीतर का यह व्यवसाय शिखर तक पहुंचने वाला है, तो किसी भी तरह से देर ना करें और कम लागत पर ही तीतर का या बिजनेस शुरू करें।

## मधुमक्खी पालन में आने वाली समस्याएं और लगने वाले रोग :

वैसे तो मधुमक्खियां खुद ही एक बेहतरीन पोलिनेटर के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए इनमें ज्यादा बीमारियां नहीं होती है, लेकिन बदलते पर्यावरणीय प्रभाव और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से फूलों में पहुंचे दूषित और केमिकल तत्व मधुमक्खियों के शरीर में चले जाते हैं, जो कि उनके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

### वरोआ माइट (Varroa mites) :

यह कीट पिछले कई सालों से मधुमक्खी की कॉलोनियों को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। यह बड़ी से बड़ी मधुमक्खियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।



केरल के मुर्गी पालकों की बड़ी समस्याएं, कहर बरपा रहा है बर्ड फ्लू



## केरल के मुर्गी पालकों की बड़ी समस्याएं, कहर बरपा रहा है बर्ड फ्लू (Bird Flu)

हर बार थोड़े-थोड़े समय में हमें बर्ड फ्लू की खबर सुनने को मिल जाती है। बर्ड फ्लू एक संक्रामक बीमारी है, जो पक्षियों को प्रभावित करती है। जबकि मनुष्य आमतौर पर इस वायरस के संपर्क में नहीं आते हैं। बर्ड फ्लू (Bird Flu) या एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के संक्रमण के कारण होने वाली स्थिति है। जो आमतौर पर जंगली जलीय पक्षियों में देखी जाती है। यह घरेलू पोल्ट्री, अन्य पक्षियों और जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है।

हाल ही में केरल राज्य में बर्ड फ्लू (Bird Flu) की खबर आ रही है और रिपोर्ट की मानें तो यहां पर लगभग 3000 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू ज्यादातर बतख और मुर्गियों को प्रभावित करता है। जिससे पोल्ट्री फार्म (Poultry Farm) में एक साथ सैकड़ों की संख्या में मुर्गियों और बतखों सहित अन्य पक्षियों की मौत हो जाती है। जब भी बर्ड फ्लू फैलता है, यह मुर्गी पालन का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए बेहद परेशानी का कारण बन जाता है। साथ ही, उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ आलम आजकल केरल के मुर्गी पालकों का है। यहां भारी मात्रा में मुर्गियों की बर्ड फ्लू से मौत हो रही है।

जानकारी के मुताबिक, केरल के तिरुवनंतपुरम जिला स्थित पेरुंगुड्डी में एक फार्म में एवियन फ्लू से 200 बतखों की मौत हो गई है। इसके बाद राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए एडवाइजरी जारी की है। वहीं, बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने तिरुवनंतपुरम में कई स्थानों पर पक्षियों को मारना शुरू किया। वार्ड सदस्यों की मदद से पेरुंगुड्डी जंक्शन वार्ड के एक किलोमीटर के दायरे में 3000 तक पक्षियों को मार गया है।

## डॉक्टर को तुरंत सूचना दें

अगर रिपोर्ट की मानें तो जिन पक्षियों को बर्ड फ्लू हुआ है उनके अंडे, मांस, चारा और गोबर का भी निस्तारण किया जा रहा है। खास बात यह है, कि सरकार ने विभाग के निगरानी क्षेत्र की घोषणा में किड्डीविलम, कडक्कूर, कीझार्टिंगल, चिरायिकीडु, मंगलापुरम, अंदूरकोणम और पोथेनकोड पंचायत को शामिल किया है। इसके अलावा इस माहौल में स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है, कि अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार आ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह इसकी सूचना तुरंत डॉक्टर को दें।

## बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षियों को संभालते हुए कैसे रखें अपना ख्याल

मुर्गियां, बतख, गीज़, बटेर, टर्की और अन्य पालतू पक्षियों को राज्य में बर्ड फ्लू होने की सूचना मिली है। हालांकि, राज्य को अभी तक लोगों में एवियन फ्लू के संक्रमण की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने उन सभी व्यक्तियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, जो मुर्गी पालन में लगे हैं या फिर किसी भी तरह से बर्ड फ्लू होने वाले पक्षियों के संपर्क में आए हैं। डॉक्टर कुछ शुरुआती इलाज करने के बाद इसके निवारण के लिए दवाइयां दे देते हैं। साथ ही, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। सभी लोगों को आदेश दिए गए हैं, कि जब भी वह बर्ड फ्लू से संक्रमित होने वाले किसी भी पक्षी को संभाल रहे हैं तो दस्ताने और मास्क पहनना ना भूलें। साथ ही, बार बार साबुन से हाथ धोने की सलाह भी दी गई है। शरीर में गंभीर दर्द, बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, सर्दी और कफ में खून आने जैसी शिकायत आने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की बात कही गई है। हालांकि बर्ड फ्लू मनुष्य को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। लेकिन फिर भी कुछ मामले देखे गए हैं, जिसमें यह बीमारी लोगों को हो सकती है। अगर इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो यह खतरनाक साबित हो सकती है।

मधुमक्खी पालकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी



## मधुमक्खी पालकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी

शहद के गुणों के बारे में कौन नहीं जानता है। प्राकृतिक मिठास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यह गुणकारी चीज घर घर में पाई जाती है। आजकल लोग भारी मात्रा में मधुमक्खी पालन करते हैं और इस व्यवसाय से काफी मुनाफा कमा रहे हैं।

आपके लिए शायद यह नई बात होगी, लेकिन मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि, बहुत से ऐसे लोग हैं, जो मधुमक्खी पालन में अड़चन बन जाते हैं। साथी ही, मधुमक्खियों की सेहत के लिए काफी हानिकारक होते हैं। हाल ही में मधुमक्खी पालन संघ के बोर्ड के मेंबर ट्रेवर टॉज़र ने सभी मधुमक्खी पालकों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर दी है। उनके अनुसार, नया टीका 'मधुमक्खी पालकों के लिए एक रोमांचक कदम' हो सकता है।





उनके द्वारा की गई बातचीत से पता चलता है, कि इस टीके का इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत महंगे उपचार करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस व्यवसाय के बाकी क्षेत्रों पर अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं।

देश दुनिया के सभी मधुमक्खी पालन करने वाले व्यवसायियों के लिए यह खबर बेहद खुशखबरी लेकर आई है। क्योंकि अब उनकी मधुमक्खियां पहले के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ रहेगी, जिससे शहद का उत्पादन भी अपने आप ही बढ़ेगा। मधुमक्खियों के लिए बने इस टीके के उपयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। इस टीके को मधुमक्खी कालोनियों को अमेरिकी फाउलब्रूड रोग से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दरअसल, फाउलब्रूड एक ऐसा रोग है, जो जीवाणु संक्रमण का एक रूप है और यह सीधा मधुमक्खी के लारवा पर हमला करता है और मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी को कमजोर कर देता है। डालन एनिमल हेल्थ के सीईओ एनेट क्लेसर ने हाल ही में हुई बातचीत में बताया कि, मधुमक्खियां एक ऐसा जीव है जो ईको सिस्टम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में इस टीके को मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए भी एक बहुत ही कामयाब पहल मानी जा रही है।

इन सबके साथ ही बायोटेक फॉर्म के अनुसार अमेरिकी कृषि विभाग ने इसी सप्ताह ही इस वैक्सीन के लिए लाइसेंस को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र एफएओ के अनुसार, मधुमक्खियों, पक्षियों और चमगादड़ों जैसे परागणकों का वैश्विक फसल उत्पादन में लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।

रिपोर्ट की मानें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी साल 2006 से मधुमक्खियों की कॉलोनियों में काफी ज्यादा कमी आई है। इसके लिए बहुत से कारक जिम्मेदार माने गए हैं। यह सभी कारक अंततः जाकर मधुमक्खी के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। बहुत से परजीवी और कीट मधुमक्खियों की सेहत के लिए काफी हानिकारक होते हैं। कई बार मधुमक्खियों को इनके कारण इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इस वैक्सीन का वितरण सभी तरह के मधुमक्खी योजना में एक योजना के अनुसार किया जाएगा



आकर्षक ऑफर्स की जानकारी के लिए "Get Offer" पर क्लिक करें



## मोटा अनाज हो सकता है आपके पशुओं के लिए घातक

हम सभी जानते हैं, कि यह साल विश्व में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स (आईवायओएम/IYoM) के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सभी तरह के मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत के लिए जनता को प्रोत्साहित कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है, कि मोटे अनाज का सेवन करना आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह न सिर्फ आपको स्वास्थ्य को अच्छा बनाकर रखता है, बल्कि यह हमारी प्रतिरक्षा (Immunity) बढ़ाने के लिए भी बेहद जरूरी है।

अगर आप नियमित रूप से मोटे अनाज का सेवन करते हैं, तो यह आपके प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune system) को स्ट्रॉंग करता है। आपको बहुत तरह के रोगों से दूर रखता है। मोटा अनाज इंसानों के अलावा पशुओं के लिए भी काफी लाभकारी माना गया है। लेकिन हमें यह भी जानने की जरूरत है, कि मोटा अनाज कभी-कभी पशुओं के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे।

## पशुओं को किस तरह से खिलाया जाए बाजरा

अगर आप अपने पशुओं के आहार में बाजरे को मिलाना चाहते हैं, तो आप इसका दलिया बनाकर उसे अच्छी तरह से पका कर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे अपने पशुओं को खिला सकते हैं। साथ ही, आप पशुओं के चारे में बाजरे का आटा मिलाकर भी उन्हें खिला सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी लेकिन पशुओं को भी थोड़े बहुत नमक की जरूरत होती है। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो आप इस आटे में चुटकी भर नमक भी मिलाकर पशुओं को दे सकते हैं। रोजाना बात की जाए तो आप 1 से 2 किलो बाजरा अपने पशुओं को खिला सकते हैं। बाजरे का आटा खिलाने का सबसे बड़ा फायदा यह है, कि यह आपके पशुओं को वजन बढ़ाने में मदद करता है।

## पशुओं को बाजरा खिलाने के क्या है फायदे

पशुओं को बहुत पहले से बाजरा या फिर बाजरे का आटा खिलाया जाता रहा है। अगर आप के पशु को लिवर से जुड़ी हुई किसी तरह की समस्या है, तो आप उसे बेझिझक बाजरा खिला सकते हैं यह उसके लिए काफी लाभदायक होगा। बाजरा पशुओं के पाचन तंत्र को मजबूत करता है। बहुत से मामलों में ऐसा होता है, कि बच्चा पैदा करने के बाद पशु बीमार रहने लगता है। ऐसे मामले में आप उसे बाजरा खिला सकते हैं। यह न सिर्फ उसे बीमारियों से दूर रखेगा बल्कि यह पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा सहायक है। आप छोटे पशुओं जैसे कि बछड़े आदि को भी बाजरे के आटे की छोटी-छोटी लोई बनाकर खिला सकते हैं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है।





## बाजरा खिलाने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं

हमने मोटे अनाज जैसे कि बाजरे आदि का पशुओं के आहार में फायदा तो देख लिया है। लेकिन कई बार इसके बहुत से नुकसान भी देखे जाते हैं। अगर आप लंबे समय तक अपने पशुओं को बाजरे का आटा या फिर बाजरे का दलिया खिलाते रहते हैं। तो उनमें आयरन की कमी हो सकती है। इससे पशु की बाँडी पर गांठें उभरने लगती हैं। इसके अलावा अगर आप जरूरत से ज्यादा बाजरा पशुओं को खिला रहे हैं, तो उनमें अफारे की समस्या देखने को मिल सकती है। पशु चिकित्सक और एक्सपर्ट का कहना है, कि कभी भी किसी जानवर को बिना डॉक्टर की सलाह के बाजरा नहीं खिलाया जाना चाहिए। अगर आप इसे खिला भी रहे हैं, तो इसकी मात्रा हमेशा सीमित रखें।



**MASSEY FERGUSON**  
**9500E**  
**50 HP**

आकर्षक ऑफर्स के लिए क्लिक करें





[www.merikheti.com](http://www.merikheti.com)



## Merikheti.com ने की जनवरी की मासिक किसान पंचायत

Merikheti.com के द्वारा 7 जनवरी 2023 दिन शनिवार को सोनीपत (हरियाणा) के गाँव टिकोला में आयोजित की गयी। मासिक किसान पंचायत के दौरान किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसलों एवं तकनीकों के बारे में बताया गया था। Merikheti.com द्वारा प्रत्येक माह किसान मासिक पंचायत का आयोजन किया जाता है। जिससे कि किसानों को वर्तमान में कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तन के बारे में बताया जा सके साथ ही उनकी आय में बढ़ोत्तरी करके उनको अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

हमारे समाज की रीढ़ के रूप में, खेती किसानी हर वर्ग को खाना दिलाकर पेट भरने वाला इकलौता व्यवसाय है। हालांकि, उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के बावजूद, किसानों को अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके कल्याण और आजीविका को प्रभावित कर सकती हैं। इन मुद्दों को हल करने और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करना महत्वपूर्ण है, जहाँ वे अपनी समस्याओं पर चर्चा करने और उनका समाधान खोजने के लिए एक साथ आ सकें।

किसानों के हित में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक मौजूद रहते हैं। किसान बेझिझक अपने सवाल पूछते हैं, जिनका उत्तर कार्यक्रम में उपस्थित कृषि विशेषज्ञ और कृषि वैज्ञानिक विस्तृत रूप में देते हैं। किसान मासिक पंचायत के दौरान डॉ. सी.बी. सिंह प्रिंसिपल साइंटिस्ट (RETD) IARI एवं डॉ. हरीश कुमार कृषि वैज्ञानिक PUSA (ICAR) सहित अन्य बहुत से कृषि क्षेत्र से जुड़े दिग्गज वैज्ञानिक उपस्थित रहे। किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ने की सलाह दी गई। इस पंचायत में मैसी फर्ग्यूसन (Massey Ferguson) से आए विशेषज्ञों ने भी बढ़चढ़कर भागीदारी दर्ज की। मैसी के विशेषज्ञों ने किसानों की ट्रैक्टर से संबंधित जिज्ञासा के बारे में भी उनको बेहतर जानकारी प्रदान की।

Merikheti.com का मुख्य उद्देश्य किसानों की बेहतरी है। इसलिए प्रत्येक माह किसान मासिक पंचायत का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन से किसानों को कृषि से संबंधित बहुत-सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। उनको फसलों के उत्तम चयन व फसलों की देखभाल किस प्रकार करें आदि आवश्यक पहलुओं के बारे में बेहद गहनता से बताया जाता है। किसान इस मासिक पंचायत में बढ़चढ़ कर हिस्सेदारी लेते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान प्रदान किया जाता है। मासिक किसान पंचायत के अंतर्गत वैज्ञानिकों से सवाल पूछने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाता है।

मेरीखेती की टीम विभिन्न राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में मासिक किसान पंचायत का आयोजन कराती है। किसान भी इन कार्यक्रमों में खूब दिलचस्पी दिखाते हैं। किसानों को बीज उत्पादन से लेकर व्यापारी बनाने तक की जानकारी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रदान की जाती है। इस मासिक किसान पंचायत में वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ किसानों को आधुनिक तकनीकों एवं कृषि प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अगर किसी किसान को कृषि संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो कार्यक्रम में उपस्थित कृषि वैज्ञानिक किसान की समस्या का सर्वोत्तम समाधान प्रदान करते हैं। यदि आप भी खेती करती हैं, तो Merikheti.com पर कृषि संबंधित सही एवं सटीक जानकारी ले सकते हैं।



## JPS DABAS जी ने किसान दिवस पर किसानों को संबोधित किया

### किसान दिवस

किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है

भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, जिसकी आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र पर आश्रित रहता है। इसी वजह से चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, कि देश की समृद्धि का रास्ता गाँव के खेतों एवं खलियानों से होकर गुजरता है। किसान दिवस के मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉ. जे.पी.एस. डबास (Dr. J.P.S. DABAS, SCIENTIST of Indian Agricultural Research Institute And the department of AGRICULTURAL EXTENSION, PRINCIPAL SCIENTIST at CATAT (Centre for Agricultural Technology Assessment and Transfer (CATAT), IARI, New Delhi-12) जी ने देशवासियों व किसानों को संबोधित करते हुए कहा है:

भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत बहुत पुरानी वह धनी है तथा इसने पुरे विश्व को प्रभावित किया है। कृषि यहां के सांस्कृतिक विकास में अग्रणी भूमिका में रहीं हैं। कृषि को यहां प्राचीन काल से ही केवल व्यवसाय के रूप में नहीं देखकर एक जीवन पद्धति के रूप में मान्यता मिली है। लेकिन मध्यकाल से पिछली शताब्दी के मध्य तक विदेशी आक्रमणकारी द्वारा भारतीय संस्कृति को अत्यधिक नुकसान पहुंचा गया इससे कृषि वह किसान की हालत काफी प्रभावित हुई। देश विदेशों पर खाद्यान्न के लिए निर्भर हो गया था।

किसान समाज को जाति, धर्म वह क्षेत्र के आधार पर बांट दिया गया। व्यापारी वर्ग वह उस समय के शासकों ने खूब आर्थिक रूप से ठगा। जिससे कृषि वह किसान की हालत जर्जर हो चुकी थी। देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी होने के बावजूद देशवासियों को विदेशों पर खाद्यान्न के लिए निर्भरता और किसानों की आर्थिक बढहाली स्वतंत्र भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी।







इस चुनौती का सामना करने में वह किसानों को जागरूक वह एकजुट और प्रौत्साहित करने के साथ साथ सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाने की जो भूमिका स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने निभाई वह अद्वितीय थी। उन्होंने कृषि वह किसान के महत्व के हर मुद्दे को बखुबी सरकार के सामने उठाने वह हल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनको पुरे भारत का किसान अपना नेता मानते थे तथा उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते थे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के लिए किसानों, कृषि वह देश के हित सर्वोपरि थे।

किसानों को समझाने के लिए वो कड़वी सच्चाई को प्रस्तुत करने में पिछे नहीं रहते थे और किसान भी उनके साथ दिल से जुड़े हुए थे। वो किसानों को जोर देकर कहते थे कि पहले तो किसानों को आपसी मतभेद भुलाकर अपने वह देश के आर्थिक विकास के लिए एक जुट होने की आवश्यकता है फिर उनको उत्पादन से अधिक विपणन वह बाजार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता आज के परिपेक्ष में और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है तथा बहुसंख्यक किसान आज भी यही मार खा रहे हैं। किसान भी उनकी एक आवाज सुनकर शान्ति पुर्ण वह अनुशासित ढंग से दिल्ली वोट क्लब पर उनकी आवाज में आवाज मिलाने के लिए पहुंच जाते थे। उनके वह किसानों के मध्य एक अजब गजब किस्म का संबंध था। इस संबंध और उनके महत्वपूर्ण कृषि, किसान वह ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सरकार ने उनके जन्मदिन 23 दिसम्बर को किसान दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया। इससे किसानों को उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है तथा किसान जाति, धर्म, क्षेत्र वह दलगत राजनीति से उपर उठकर काम करने की प्रेरणा लेते हैं। आज हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं तथा सभी देशवासियों को आवान करते हैं कि हमें उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए और देश, समाज की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। किसान वह कृषि के हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़े।



देश में गेहू के भाव में निरंतर बढ़ोत्तरी का क्या कारण है।

## देश में गेहू के भाव में निरंतर बढ़ोत्तरी का क्या कारण है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ विभिन्न राज्यों में अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश भी गेहू का एक अच्छा उत्पादक राज्य है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गेहू का भाव 3050 रुपए प्रति क्विंटल है। हालात ऐसे हो गए हैं, कि सबसे बड़े गेहू उत्पादक राज्य की पहचान रखने वाला उत्तर प्रदेश गुजरात से गेहू खरीद रहा है। जबकि इसी अनाज का भाव राजस्थान राज्य में 2800 रुपए प्रति क्विंटल है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो रूस व यूक्रेन युद्ध की वजह से विभिन्न देशों में गेहू की खाद्य आपूर्ति काफी प्रभावित हुई है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार दिल्ली जैसे राज्यों में गेहू की कीमत 3000 के पार हो चुकी है। इस वजह से पूर्वी भारत क्षेत्रों में गेहू की उपलब्धता में कमी देखने को मिली है। केंद्र सरकार द्वारा गेहू को खुले बाजार में बेचने की योजना जारी करने में ढिलाई बरती है, नतीजतन गेहू के भाव में निरंतर बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हेतु गेहू का आवंटन बाधित कर दिया है, जो कि इस समस्या का कारण बना हुआ है।

गेहू की उपलब्धता को लेकर उत्तरी सूबा भी काफी समस्याओं से जूझ रहा है। कृषि एगामार्केट द्वारा प्रेषित आंकड़ों के अनुरूप 8 जनवरी को गेहू का भाव 2788 रुपए प्रति क्विंटल हो गया था। विगत वर्ष के तुलनात्मक यह भाव 20 प्रतिशत ज्यादा है। अगर हम उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें, तो गेहू का मूल्य खुदरा बाजार में 31.17 किलो है विगत वर्ष की तुलना में 18.5 फीसद की बढ़त दर्ज हुई है। गेहू का भाव 2022 के रबी सीजन में निर्धारित एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल होने के बाद निरंतर बढ़े हैं। वर्ष 2023 में एमएसपी 2125 रुपए हो गई है।

एक ट्रेड विश्लेषण के तहत गेहू के साथ चावल की आपूर्ति संबंधित समस्या सामने आयी है। इस वजह से पैदावार के आंकड़ों पर भी शक जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल ने अनाज खरीदी का 60 लाख टन अनाज खरीदने का लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद माल 20 लाख टन ही गेहू की खरीद कर पाया है।

ट्रेड विशेषज्ञों के अनुसार अनाज के भावों में निरंतर बढ़ोत्तरी साबित कर रही है कि महंगाई दर भी बढ़ रही है। साथ ही, गेहू की कीमत आगामी उपज तक 3300 रुपये प्रति क्विंटल तक होने के आसार हैं। यही दशा फरवरी माह के समापन या मार्च के आरंभ तक ऐसी ही बनी रहेगी। उस समय तक गुजरात में गेहू की नवीन पैदावार बाजार में आ चुकी होगी। आरएफएमएफआई के प्रमोद कुमार का कहना है, कि उत्तर प्रदेश एवं बाकी के उत्तरी राज्यों में गेहू के फसल की आवक मार्च माह के समापन तक आरंभ होगी। इस स्थिति में केंद्र सरकार को अपने भंडारण से ओएमएसएस योजना के अनुरूप अनाज विक्रय किया जा सकता है। गेहू कारोबारियों के अनुसार केंद्र सरकार खासकर पीएमजीकेएवाई को देखते हुए बाजार पर करीबी नजर बनाए हुए है।



इफको कंपनी द्वारा निर्मित इस जैव उर्वरक से किसान फसल की गुणवत्ता व पैदावार दोनों बढ़ा सकते हैं



## इफको (IFFCO) कंपनी द्वारा निर्मित इस जैव उर्वरक से किसान फसल की गुणवत्ता व पैदावार दोनों बढ़ा सकते हैं

भारत के दक्षिणी-पूर्वी समुद्री तटों में उगने वाले लाल-भूरे रंग के शैवाल भी फसल की गुणवत्ता के साथ पैदावार में बढ़ोत्तरी हेतु भी काफी सहायक साबित होते हैं। इफको (IFFCO) द्वारा इस समुद्री शैवाल के प्रयोग से जैव उर्वरक भी निर्मित किया जाता है। कृषि क्षेत्र को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने हेतु केंद्र व राज्य सरकारों एवं वैज्ञानिक निरंतर नवीन प्रयोग करने में प्रयासरत रहते हैं। खेती-किसानी के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के साथ मशीनों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इनका उपयोग करने के लिए कृषकों को अधिक खर्च वहन ना करना पड़े। इस वजह से बहुत सारी योजनाएं भी लागू की गयी हैं और आज भी बनाई जा रही हैं। इन समस्त प्रयासों का एकमाल लक्ष्य फसल की गुणवत्ता एवं पैदावार में बेहतरीन करना है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए फसलीय पैदावार अच्छी दिलाने में जैविक खाद व उर्वरक स्थायी साधन की भूमिका निभा रहे हैं। जैविक खाद तैयार करना कोई कठिन कार्य नहीं है।

किसान अपनी जरूरत के हिसाब से अपने गांव में ही जैविक खाद निर्मित कर सकते हैं। परंतु, मृदा का स्वास्थ्य एवं फसल के समुचित विकास हेतु कुछ पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसको उर्वरकों के उपयोग से पूर्ण किया जाता है। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यह है, कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मृदा की शक्ति पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

इसलिए ही जैव उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने और उपयोग में लाने की राय दी जाती है। समुद्री शैवाल जैव उर्वरक का अच्छा खासा स्रोत माना जाता है। जी हां, भारत में नैनो यूरिया (Nano Urea) एवं नैनो डीएपी (Nano DAP) को लॉन्च करने वाली कंपनी इफको ने समुद्री शैवाल के प्रयोग से बेहतरीन जैव उर्वरक (Bio Fertilizer) निर्मित किया है। जो कि फसल की गुणवत्ता एवं पैदावार को अच्छा करने में काफी सहायक माना जा रहा है।

## इफको (IFFCO) 'सागरिका' को किस तरह से तैयार करता है

देश के दक्षिण-पूर्वी तटों से सटे समुद्र में उत्पन्न होने वाले लाल-भूरे रंग के शैवालों के माध्यम से इफको ने 'सागरिका' उत्पाद निर्मित किया है। इसकी सहायता से पौधों की उन्नति व विकास के साथ-साथ फसलीय उत्पादन की बढ़ोत्तरी में काफी सहायता प्राप्त होती है। इफको वेबसाइट पर दी गयी जानकारी के मुताबिक, इफको के सागरिका उत्पाद में 28% कार्बोहाइड्रेट, प्राकृतिक हार्मोन, समुद्री शैवाल, प्रोटीन सहित विटामिन जैसे कई सारे पोषक तत्व उपलब्ध हैं।

## 'सागरिका' से क्या क्या लाभ होते हैं

इफको की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, समुद्री शैवाल से निर्मित सागरिका का विशेष ध्यान फसल की गुणवत्ता में बेहतरी लाना है। इसकी सहायता से फल एवं फूल का आकार बढ़ाने, प्रतिकूल परिस्थितियों में फसल का संरक्षण, मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने एवं पौधों की उन्नति व विकास हेतु आंतरिक क्रियाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। किसान इसका जरूरत के हिसाब से फल, फूल, सब्जियों, अनाज, दलहन, तिलहन की फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं।

## सागरिका जैविक खेती हेतु काफी लाभदायक होता है

बहुत सारे किसान वर्षों से रसायनिक कृषि करते आ रहे हैं। इसलिए वह एकदम से ऑर्गेनिक खेती (Organic Farming) की दिशा में बढ़ने से घबराते हैं। क्योंकि किसानों को फसलीय उत्पादन में घटोत्तरी का काफी भय रहता है। इस प्रकार की स्थिति में इफको सागरिका किसानों के लिए काफी हद तक सहायक भूमिका निभा सकता है। यह एक रसायन रहित उर्वरक व पोषक उत्पाद है, जो कि फसल को बिना नुकसान पहुंचाए उत्पादन को बढ़ाने में कारगर साबित होता है। किसान हर प्रकार की फसल पर इफको सागरिका का दो बार छिड़काव कर सकते हैं। विशेषज्ञों की मानें तो 30 दिन के अंतर्गत सागरिका का छिड़काव करने से बेहतर नतीजे देखने को मिलते हैं। यह तकरीबन 500 से 600 रुपये प्रति लीटर के भाव पर विक्रय की जाती है। किसान एक लीटर सागरिका का पानी में मिश्रण कर एक एकड़ फसल पर छिड़काव किया जा सकता है।



# प्रगतिशील किसान

इस राज्य की आदिवासी महिलाएं गोबर से पेंट बनाकर आत्मनिर्भर बन रहीं हैं



## इस राज्य की आदिवासी महिलाएं गोबर से पेंट बनाकर आत्मनिर्भर बन रहीं हैं

भारत की छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आदिवासी महिलाओं की उन्नति एवं प्रगति के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार की मदद से आदिवासी महिलाओं का संगठन गोबर द्वारा पेंट निर्मित किया जा रहा है। इसको बेहद सराहना प्राप्त हो रही है। केंद्र व राज्य सरकार पूर्णतया कृषक, महिलाओं के विकास हेतु निरंतर कार्य कर रहे हैं। भारत में ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां काफी संख्या में आदिवासी महिलाएं रहती हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारें उनको भी मुख्यधारा में लाने के लिए कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य प्रदेश माना जाता है। यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर ज्यादा आश्रित होती है। परंतु, फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य की आदिवासी महिलाएं अच्छी-खासी खेती कर रही हैं।

## छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं का समूह बना रहा प्राकृतिक पेंट

छत्तीसगढ़ सरकार की मदद एवं प्रोत्साहन के माध्यम से आदिवासी महिलाएं विकास की दिशा में अग्रसर हो रही हैं। प्रदेश की आदिवासी महिलाएं गोबर का प्रयोग कर प्राकृतिक पेंट निर्मित कर रही हैं। बता दें कि कांकेर जनपद में वनांचल के अंतर्गत गांव सराधु नवागांव के गौठान में स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। यह पेंट बनने का कार्य तीव्रता से हो रहा है, साथ ही बाजार में भी इसकी खपत में बढ़ोत्तरी हुई है।

## आदिवासी महिलाओं के समूह ने कितने लीटर पेंट बना लिया है

छत्तीसगढ़ राज्य की आदिवासी महिलाओं के संगठन द्वारा गोबर का उपयोग कर प्राकृतिक पेंट बनाकर बेचा जा रहा है। न्यूनतम समयांतराल में महिलाओं द्वारा 5000 लीटर माला से भी ज्यादा पेंट निर्मित किया जा चुका है। महिलाओं ने उस पेंट को बेचकर आमदनी भी करली है। राज्य की महिलाओं के गोबर से बने पेंट की विधि को जानने के लिए समीपवर्ती जनपदों से लोगों का ताँता लगा रहता है।

## इस प्राकृतिक पेंट का कितना मूल्य है

आदिवासी महिलाओं के इस प्राकृतिक पेंट का मूल्य बाजार में उपलब्ध प्रीमियम क्वालिटी के पेंट के तुलनात्मक 40 फीसद तक कम है। क्योंकि बाजार में बिकने वाले पेंट काफी महंगे मिलते हैं। आदिवासी महिलाओं के प्राकृतिक पेंट की विशेषताओं की बात की जाए तो यह नॉन टॉक्सिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटीफंगल, इको-फ्रेंडली (Eco-friendly) भी होता है। इन समस्त विशेषताओं की वजह से प्राकृतिक पेंट की खरीद काफी बढ़ गयी है।



## जाने खेती के साथ-साथ बिजली उत्पादन करते हुए कैसे कमा रहे हैं किसान ज्यादा आमदनी

खेती करते हुए किसान खेती के साथ-साथ अलग-अलग तरह के व्यवसाय करते रहते हैं। ताकि उन्हें और ज्यादा आमदनी होती रहे और आर्थिक तौर पर वह मजबूत बने रहे। आपने खेती-बाड़ी के साथ-साथ पशुपालन या फिर फूलों आदि की खेती के बारे में तो जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी खेती के साथ बिजली उत्पादन करते हुए किसानों को लाभ कमाते देखा है।

आजकल के आधुनिक दौर में क्या कुछ मुमकिन नहीं है। इसी तरह से किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल सरकार की तरफ से की गई है। इसमें किसान खेती के साथ-साथ बिजली उत्पादन करते हुए लाभ कमा सकते हैं। इस स्कीम के तहत सबसे अच्छी बात है, कि सरकार खुद किसानों को इसके लिए प्रेरित कर रही है और अच्छी खासी मदद भी दे रही है।

अब सौर ऊर्जा को प्रमोट करते हुए खेत में सोलर पंप से लेकर सोलर प्लांट लगवाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। जिससे कृषि कार्यों के लिए खेतों से ही बिजली मिल जाए। साथ में, बिजली कंपनियों को भी बिजली को बेचकर अतिरिक्त आमदनी हो जाए। उत्तर प्रदेश में भी जल्द किसानों को ऐसी ही एक योजना का लाभ मिलने वाला है।

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 6 जिलों में प्राइवेट डेवलपर्स यानी किसानों के साथ बिजली को खरीदने के लिए एक समझौता किया है। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है और यह पीएम कुसुम योजना के तहत लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत 7 मेगावाट सोलर पावर जेनरेशन प्रोजेक्ट को गति देने के लिए किया गया है।

## कैसे होगी किसानों की आमदनी

अगर किसानों की भूमि बंजर और अनुपयोगी है, तो उत्तर प्रदेश के किसान अपनी भूमि पर सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं। यह सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए किसानों को तमाम तरह के बैंक और वित्तीय संस्थाएं पूरी तरह से मदद करेंगे। इसके अलावा इस योजना के तहत आप सरकार से सब्सिडी भी ले सकते हैं। ताकि आपको शुरुआती समय में ज्यादा खर्च ना करना पड़े।





इतना ही नहीं, किसान अपने खेतों में लगे सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन लेकर ना सिर्फ कृषि कार्यों को बिना किसी खर्च में पूरा कर सकते हैं। बल्कि प्राइवेट बिजली कंपनियों को बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी कमा सकते हैं। फिलहाल, सौर बिजली उत्पादन की सुविधा यूपी के बिजनौर, हाथरस, महोबा, जालौन, देवरिया और लखनऊ में दी जाएगी।

## कितना होगा बिजली उत्पादन

यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम. देवराज ने बताया है, कि बिजनौर के विलासपुर गांव में 1.5 मेगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र बनाया जाएगा।

हाथरस के मौहारी गांव में 0.5 मेगावाट और देवगांव के गांव में 1 मेगावाट की सुविधा दी जाएगी। महोबा और जालौन के खुकसिस गांव में 1 मेगावाट और बरियार गांव में 1 मेगावाट की सुविधा वाला सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र बनाने का प्लान है।

यहां पर किसानों को दो तरह के विकल्प दिए गए हैं। पहला या तो वह डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी सिंचाई पंप में अपग्रेड करवा सकते हैं या फिर अपने खेत में सोलर प्लांट लगवाने की व्यवस्था कर सकते हैं। कमाई की बात की जाए, तो इस तरह से लगे हुए सोलर पावर प्लांट से किसान सालाना लगभग 80,000 रुपये तक कमा सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से किसानों को सोलर पंप की लागत पर 90 फीसदी सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

## क्या है पीएम कुसुम योजना

पीएम कुसुम योजना के तहत 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगवाने के लिए लगभग 5 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। वहीं पर अगर आप 0.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं, तो यह केवल 1 एकड़ जमीन में भी किया जा सकता है।

इस योजना के तहत किसानों को सबसे बड़ा फायदा यह है, कि उन्हें स्वयं भी किसी तरह की बिजली से जुड़ी हुई समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। साथ ही, वह बनने वाली एक्स्ट्रा बिजली को बेचकर ज्यादा आमदनी भी कमा सकते हैं। जिससे उनके आर्थिक हालात सुधारने में बेहद मदद मिलेगी।



आकर्षक ऑफर्स की जानकारी के लिए "Get Offer" पर क्लिक करें

